

तीन सप्ताह की छुट्टी के बाद, राहुल गांधी अपने देश लौटे

भाजपा में काफी जिज्ञासा व उत्कण्ठा है कि राहुल कांग्रेस व देश के सम्मुख प्रस्तुत गहन समस्याओं के बावजूद इतनी बेफ़्रिकी से विदेश कैसे निकल जाते हैं

-रेणु मिश्रल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 जुलाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगभग तीन सप्ताह के राजनीतिक अवकाश के बाद दिल्ली लौट आए हैं। अवकाश के दौरान उन्होंने राजनीति की व्यस्तताओं से दूर रहकर फीफा विश्व कप का एक मैच देखा, स्कैंडिनेवियाई देशों की यात्रा की और कुछ समय विश्राम किया।

लेकिन, भारतीय जनता पार्टी को यह सब पच नहीं रहा है। उसने राहुल गांधी के इस विदेश दौरे को लेकर उन पर निशाना साधा है। भाजपा सवाल उठा रही है कि कांग्रेस और विपक्ष के सामने मौजूद अनेक चुनौतियों के बावजूद, राहुल गांधी इतने लंबे समय तक विदेश में समय कैसे बिता सकते हैं।

कांग्रेसी सूत्रों का कहना है कि क्या भाजपा को इस बात की चिन्ता नहीं होनी चाहिए कि जब देश के भीतर अनेक

- राहुल गांधी ने हाल ही में इन छुट्टियों में फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच देखे और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आनंदपूर्वक भ्रमण करके लौटे हैं। भाजपा का कटाक्ष है, क्या उनके आगमन के इंतज़ार में समस्याएं व मुद्दे “कोल्ड स्टोरेज” में शांति से ठंडी हवा खाते रहेंगे?
- कांग्रेस का खेमा जवाबी ताना मार रहा है, प्र.मंत्री ने देशवासियों को मितव्ययता और विदेश यात्रा पर न जाने की सलाह दी, पर वे स्वयं इस परामर्श का खुला उल्लंघन करते हुए, एक के बाद एक विदेश यात्राओं का सिलसिला जारी रखे हुए हैं।
- राजनीतिक हल्कों की चर्चाओं के अनुसार, राहुल 17 जुलाई को देहरादून जाएंगे तथा उसी के बाद, कांग्रेस पूरी तरह से हरकत में आएगी।

गंभीर समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार विदेश यात्राओं में इतना समय क्यों व्यतीत करते हैं।

ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े जोर-शोर से देशवासियों से अपील की थी कि वे विदेश यात्राओं से बचें, कम से कम खर्च करें और भविष्य के

लिए बचत करें।

राहुल गांधी के सामने इस समय पार्टी के भीतर विभिन्न चुनौतियों के साथ-साथ, विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकजुटता को लेकर महत्वपूर्ण रणनीति तैयार की जानी है।

इसके अलावा, कांग्रेस नेतृत्व को राजधानी दिल्ली सहित, कई राज्यों में उत्पन्न राजनीतिक और संगठनात्मक परिस्थितियों से भी निपटना है। सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून का दौरा करेंगे। इसके बाद उनके अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी।

सरकार ने नवम्बर तक पंचायत-निकाय चुनाव नहीं करा पाने के कारण बताये

जयपुर, 13 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराने की समय सीमा निर्धारित करने के सम्बंध में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र में नवंबर

- हाई कोर्ट में संयम लोढ़ा की अवमानना याचिका पर सुनवाई आज।

तक चुनाव नहीं करा पाने के कारण बताए गए हैं। वहीं दूसरी ओर, मामले में संयम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ सुनवाई करेगी। राज्य सरकार की ओर से समय बढ़ाने के लिए दायर प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में करीब पचास फीसदी आबादी ओबीसी वर्ग की है। ऐसे में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नई व्यवस्था के बारे में वे कहते हैं, “अब लाइसेंस लेने के लिए किसी अफसर या नेता के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें किसी व्यक्ति का कोई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सड़क दुर्घटना में कानोड गाँव के 5 युवकों की मौत

बालोतरा, 13 जुलाई (निस)। जिले के पंचपदरा थाना क्षेत्र में देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग-125 पर भांडियावास गांव के पास हुए भीषण सड़क हादसे में गिड़ा क्षेत्र के कानोड गांव के पांच युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

जानकारी के अनुसार, कानोड गांव के आठ दोस्त स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर पडासला स्थित भोमियाजी के दर्शन करने गए थे। दर्शन करने के बाद

- आठ दोस्त भोमियां जी के दर्शन कर स्कॉर्पियो से वापस लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गए।

सभी देर रात अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान भांडियावास गांव के पास उनकी स्कॉर्पियो पहले तो एक अज्ञात वाहन से टकराई और फिर अनियंत्रित होकर आगे चल रहे डंपर में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में रेवांतराम (26) पुत्र गेनाराम जाट, स्वरूपाराम (27) पुत्र मेहराराम जाट, भरत (25) पुत्र बन्नाराम जाट, किशन (27) पुत्र शेराराम जाट तथा भावेश पुत्र कलाराम जाट की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोशल मीडिया ने नितिन गडकरी व उनके परिवार को भी नहीं बख्शा

बार-बार सवाल उठ रहा है कि क्या गडकरी ने एथेनॉल मिलाने की नीति अपने पारिवारिक बिज़नेस को बढ़ाने के लिए शुरू की है

-श्रीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 जुलाई। केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, जो एथेनॉल बनाने वाली बड़ी कंपनी “सियान एग्रो इंडस्ट्रीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड” में अपने बेटे निखिल गडकरी की बड़ी हिस्सेदारी को लेकर जांच के दायरे में हैं, ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की ई-20 नीति का जोरदार बचाव किया है।

हाल के दिनों में उपभोक्ताओं की शिकायतें बढ़ी हैं। इनमें एथेनॉल के कारण वाहन के पुर्जों में जंग लगने की आशंका, एथेनॉल की कैलोरी वैल्यू कम होने के कारण माइलेज घटने और पुराने वाहनों में आने वाली दिक्कतें शामिल हैं। विवाद तब और बढ़ गया, जब ऐसी खबरें सामने आई कि ई-20 को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- लेकिन गडकरी ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया और कहा, उनके परिवार का चीनी व एथेनॉल उद्योग से पुराना नाता है, और इस नीति से उन्हें व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ है।
- गडकरी ने कहा, पेट्रोलियम लॉबी व उनके राजनैतिक विरोधी उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना राष्ट्रीय हित में है। इससे कच्चे तेल का आयात कम होगा, प्रदूषण कम होगा और गन्ना किसानों को लाभ होगा। अमेरिका, ब्राज़ील व थाईलैंड में यह नीति सफल हो चुकी है।

- विरोधी लॉबी का कहना है कि पेट्रोल-डीज़ल में एथेनॉल मिलाने की नीति चालू करने के बाद से गडकरी के पुत्र निखिल गडकरी की कंपनी सीआईएएन एग्रो की आय में भारी वृद्धि हुई है। विरोधी पक्ष का आरोप है कि पेट्रोल-डीज़ल में एथेनॉल मिलाने से गाड़ियों के इंज़न खराब हो रहे हैं और माइलेज घट रहा है।

अब लड़ाई अमेरिका, ईरान के बीच, इज़रायल तो पिक्चर में भी नहीं

क्योंकि जंग होर्मुज़ स्ट्रेट के मसले पर है, जिसे अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मार्ग मानता है, पर, ईरान इस पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहा है

-अंजन रॉय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 जुलाई। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर खुला युद्ध छिड़ गया है। दोनों पक्ष एक-दूसरे के सैन्य एवं रणनीतिक ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। युद्धरत पक्षों के बीच शांति समझौते और युद्धविराम को लेकर कतर में चल रही वार्ता फिलहाल ठप हो गई है।

पिछले चौबीस घंटों में अमेरिका ने ईरान के अरंदरूनी क्षेत्रों में सैन्य हमले किए हैं। वहीं, ईरान का दावा है कि उसने बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी सैन्य परिसंपत्तियों को निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान का कहना है कि इन देशों में तैनात कई पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों को पूरी

- इसी के चलते, ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर रहे दो जहाज़ों पर हमला कर दिया। यहीं नहीं अन्य देशों के जहाज़ों पर ईरान के हमले में कई भारतीय नाविक मारे गए। जिसकी भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आलोचना की थी।

- अमेरिका ने अब ईरान के सैन्य संस्थापनों के साथ-साथ नागरिक ठिकानों पर भी हमला शुरू कर दिया है। इसके जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन आदि देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों व तेल के कुओं को निशाना बनाया है।

तरह नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा, तेल भंडारण केन्द्रों और अन्य बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया गया है।

पिछले पंद्रह दिनों की घटनाओं पर नज़र डालें तो स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों

तेज करता दिखाई दे रहा है। होर्मुज़ स्ट्रेट में अन्य देशों के जहाज़ों पर ईरान के हालिया हमलों के कारण अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों में कार्यरत कई भारतीय नाविकों की मौत हो गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों और भारतीय नाविकों की मृत्यु को कड़ी निंदा करते हुए बयान जारी किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यह संघर्ष मुख्य रूप से अमेरिका और ईरान के बीच सीमित हो गया है, जिसमें इज़रायल की प्रत्यक्ष भूमिका दिखाई नहीं दे रही है। टकराव का केन्द्र अब होर्मुज़ स्ट्रेट बन गया है। अमेरिका इसे एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग मानता है, जबकि ईरान इसे अपने राष्ट्रीय नियंत्रण (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सीमा के समीप बने ढांचों की जाँच होगी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 13 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर बनाई गई इमारतों को हटाने से संबंधित राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के नोटिस के खिलाफ कई रिट याचिकायें दायर की। इस मामले पर सुनवाई करते हुये न्यायधीश समीर जैन ने आदेश पारित करते हुए कहा कि यह भारत की सीमा और सुरक्षा से संबंधित है और ऐसे

- हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि भारत-पाक सीमा के करीब बने ढांचों को हटाने से संबंधित जाँच हेतु कमेटी बनाई जाए।

मामलों में न्याय से बढ़कर व्यावहारिक तथा और हालात जांचकर कदम उठाने चाहिये। अदालत ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और बॉर्डर सिक््युरिटी फोर्स (बीएसएफ) के प्रतिनिधियों की कमेटियां गठित करने के आदेश दिये हैं। जो सीमावर्ती जिलों में ऐसी संवेदनशील इमारतों को चिन्हित करें हटाने का कार्य कर सकती है।

उन्होंने कहा कि इस कमेटी के सदस्य देश की सुरक्षा को देखते हुए, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘न्यायधीशों ने अपना फैसला तो सुना दिया है पर उसको लागू करने के लिए अदालत को अधिकारी कहां से मिलेंगे!’

अमरीकी राष्ट्रपति एण्ड्रू जैक्सन ने यह तथाकथित टिप्पणी तब की थी जब अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1832 में नेटिव अमेरिकन्स के पक्ष में फैसला देते हुए कहा था कि वह अपनी मूल जमीन के मालिक हैं और उन्हें अपनी जमीन से निकाला नहीं जा सकता

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 13 जुलाई। जब एक मामले पर फैसला सुनाने में कई वर्ष निकल जाए तो ऐसे विलम्बित आदेश से न्याय होता है या फिर सिर्फ कानूनी पेचीदगियां ही बढ़ती है। ऐसा ही एक जनहित से जुड़ा मामला सामने आया, जिसमें अंतिम फैसला सुनाने में अदालत को एक दशक से भी ज्यादा लगा और फिर दिये गये फैसले को कानूनी पेचीदगियों के चलते वापस लेना पड़ा और अंतोगत्वा बिल्कुल ही विपरीत फैसला हुआ।

इससे सवाल उठता है कि अदालत के समक्ष लंबी और गहन सुनवाई के बाद भी न्याय नहीं हो पाता, क्योंकि न्याय करने की प्रक्रिया में ही बहुत देरी होती है और इस देरी से न्याय का कोई अर्थ नहीं रहता।

दरअसल वर्ष 2012 में हाई कोर्ट की एक खंडपीठ के समक्ष एक जनहित याचिका पेश हुई थी। यह जनहित याचिका जयपुर सांगानेर और उसके आसपास की कॉलोनियों के निवासियों

द्वारा दायर की गई थी। जनहित याचिका में बड़े ही सीधे-सादे शब्दों में एक मुद्दा उठाया गया था कि सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हल्दीघाटी रोड से जोड़ने के लिए जयपुर के मास्टर प्लान में सौ फीट चौड़ी रोड दर्शायी गई है परन्तु इस सौ फीट चौड़ी रोड का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है, क्योंकि सड़क के किनारे और कई कई जगह पूरी सड़क पर ही अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है। अतः याचिकाकर्ताओं ने अदालत से गुहार की थी कि वो प्रशासन को अतिक्रमण हटाने और सौ फीट रोड का निर्माण पूरा करने का आदेश दे। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया था कि चूंकि सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और उसपर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है तो न तो उन्हें सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का और न ही हल्दीघाटी रोड के लिए रास्ता मिलता है। उन्हें जयपुर टोंक हाईवे का इस्तेमाल करना पड़ता है।

मामले की अलग-अलग हुई सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि

- ऐसा ही एक किस्सा राजस्थान हाई कोर्ट के समक्ष उजागर होता हुआ दिख रहा है। यह मामला सांगानेर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हल्दीघाटी रोड को जोड़ रही सौ फीट रोड से संबंधित है।
- अदालत 2012 के बाद से कई बार आदेश में कह चुकी है कि मूल नक्शे के अनुसार ही सौ फीट रोड बनाई जाए और अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए। यही जनहित का कार्य है।
- इन्हीं आदेशों के चलते अदालत ने जेडीए, हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम को 2015 में 15 महीनों की मोहलत दी थी अतिक्रमणकारियों को हटाने और निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए। परन्तु, जेडीए द्वारा अतिक्रमण तो नहीं हटाया गया उल्टे अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज करने की कार्यवाही अवश्य 2017 तक पूरी कर ली गई।
- हालत यह है कि वर्ष 2025 में भी जेडीए पहले तो निर्माण कार्य पूरा करने के लिए समय मांगता रहा फिर सड़क का अलाइनमेंट बदलने के लिए निर्णय भी ले लिया। अदालत ने इस निर्णय की निंदा की और जेडीए को फटकार लगाई लेकिन फिर तकनीकी कारणों के कारण अदालत को आदेश वापस लेना पड़ा। अब नई अदालत में सुनवाई के बाद जेडीए के सड़क अदालत को रिअलाइनमेंट के फैसले को अनुमति भी दे दी गई।

उक्त सौ फीट रोड का निर्माण मुख्य तौर पर हाउसिंग बोर्ड द्वारा अवाप्त की गई जमीन पर होना था।

हाउसिंग बोर्ड द्वारा अदालत में माना गया कि सड़क निर्माण के लिए निर्धारित जमीन पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा

30-40 प्रतिशत हिस्सा जे.डी.ए. द्वारा अवाप्त की गई जमीन पर होना था। हैरानी की बात यह है कि वर्ष 2013 में

है और वह पुलिस विभाग को तीन बार पत्र लिख चुका है कि वह अतिक्रमणकारियों को हटाने में बोर्ड की मदद करे। अदालत में इसी समय के आसपास जेडीए कमिश्नर द्वारा भी एक शपथ पत्र पेश किया गया, जिसमें उन्होंने माना कि अजय मार्ग एक्सटेंशन रोड करीबन 1.8 कि.मी. लंबी है और इसके आसपास जेडीए कॉलोनी और शिवपुरी कॉलोनी ही नियमित कॉलोनी हैं, अन्य पांच कॉलोनियां अनियमित और गैरकानूनी हैं। उन्होंने कहा कि नक्शे में उक्त सड़क की चौड़ाई सौ फीट दर्शायी गई है परन्तु वास्तविकता में कुछ जगहों पर यह केवल 3.7 मीटर से लेकर 7.5 मीटर तक ही रह गई है।

इन सब तथ्यों को जानने के बाद अदालत ने वर्ष 2015 में ही जेडीए को आदेश दिये थे कि वह अतिक्रमणकारियों द्वारा बनाई गई इमारतों को चिन्हित करे और साथ ही हाउसिंग बोर्ड को भी आदेश दिए गए थे कि वह अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करे, परन्तु ज़मीनी स्थिति बदलने और

सड़क का अलाइनमेंट बदलने के कारण अदालत में तोड़-फोड़ की कार्यवाही रोकने के लिए कई याचिकाएं दायर की गईं।

मामले की पेचीदगियों को देखते हुए अदालत ने 2015 में महाधिवक्ता से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। अदालत ने यह भी आदेश दिए थे कि जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम और शहरी विकास विभाग मीटिंग कर इस समस्या को सुलझाएं और एक एक्शन प्लान तैयार करें। अदालत ने जेडीए को अलग से यह आदेश भी दिए थे कि वह सड़क के अलाइनमेंट बदलने के मुद्दे पर कार्य करे और 15 महीने में सड़क निर्माण का कार्य पूरा करे। दूसरी ओर उन कॉलोनियों के निवासियों द्वारा अदालत में याचिका पेश कर सड़क के अलाइनमेंट को बदलने की गुहार की गई थी, क्योंकि घरों व दुकानों के निर्माण कर लिये गये थे और उनमें से कइयों के पास पंचायत के पट्टे थे।

हैरानी की बात है कि वर्ष 2017 (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

दुरात्मा के लिए देश भक्ति अंतिम शरण है। - जॉन्सन

आंकड़ों की सच्चाई से सरकार क्यों घबराई?

आज हम सरकार का मूल्यांकन केवल आरोपों–प्रत्यारोपों के आधार पर करने के बजाय, ठोस आंकड़ों के आधार पर करने का प्रयास करेंगे, जिनमें से कई स्वयं सरकार के अपने ही आंकड़े हैं। हमें यह समझना होगा कि हम कितना ही स्वयं का गुणगान कर लें, आत्म मुग्ध हो जाएं, बड़े-बड़े विज्ञापन छपवा लें, हेडिंग लगावा लें, किंतु सच्चाई तो उन आंकड़ों से ही प्रकट होती है जो धरातल से एकत्रित किए जाते हैं। इस लेख में हम ऐसे ही कुछ आंकड़ों की बात करेंगे जो हमें सच्चाई से रूबरू करते हैं।

गत कई वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी एवं सत्ताधारी दल के नेता लगातार यह दावा करते रहे हैं कि भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि में बहुत सुधार हुआ है और भारत बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। अन्य देश भारत को बहुत आदर के साथ देखने लगे हैं।

किसी भी देश की अंतरराष्ट्रीय ताकत कितनी है या उसके बारे में अंतरराष्ट्रीय जगत का क्या दृष्टिकोण है, यह परिलक्षित होता है उस देश के पासपोर्ट की ताकत से। इस ताकत को नापा जाता है “ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स” से। इस सूचकांक में भारतीय पासपोर्ट की वर्तमान रैंकिंग विश्व में 125वें स्थान पर है जबकि यह 2014 में 76वें तथा 2021 में 90वें स्थान पर थी। स्पष्ट है, भारतीय पासपोर्ट 2014 से लगातार कमजोर होता जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीयों को लगभग सभी देशों में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय है कि घाना, नामीबिया और ट्यब्यूनीशिया जैसे देशों को पासपोर्ट रैंकिंग भी भारत से बेहतर है। सरकार को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि भारत की रैंकिंग खराब हो रही है और यहां के नागरिकों के लिए बाहर जाना अधिक कठिन हो रहा है। इससे यहां के लोगों के अवसर भी कम हुए हैं।

भारतीयों के न्यूजीलैंड जाने के वीजा प्रार्थना पत्रों में से लगभग 25 प्रतिशत अस्वीकार कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के वीजा प्रार्थना पत्र में से 15 प्रतिशत खारिज हो जाते हैं। शायद यही कारण है कि कई भारतीय दंपति अमेरिका में जाकर बच्चों को जन्म देते हैं ताकि वे अमरीकी पासपोर्ट के साथ बड़े हों और उनके लिए भविष्य में विभिन्न देशों की यात्रा करना अधिक सुलभ और सुगम हो सके। पासपोर्ट रैंकिंग में विश्व में 125 नंबर पर गिरकर,भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर अग्रसर है, इस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है। सरकार को इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता है। किसी भी देश की समृद्धि का पैमाना केवल उसकी जीडीपी नहीं होता है क्योंकि जीडीपी तो जनसंख्या पर निर्भर करती है। भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय लगभग 22000 रुपए प्रति माह है। यह भारत के सभी राज्यों में बहुत असमान है। जहां दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 50000 महीने है, वहीं बिहार में यह 7700 प्रतिमाह है। “अपर मिडल इनकम ग्रुप” में भारत के केवल पांच राज्य आते हैं जिनकी वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 450000 रुपए से अधिक है। ये राज्य हैं– दिल्ली, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात। यदि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि से तुलना करें तो स्पष्ट होता है कि भारत के राज्यों में ही कितनी असमानता है? जिन राज्यों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक व्यय किया गया और जहां पर आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ किया गया, वहां पर निवेश भी हुआ और रोजगार के अवसर भी बढ़े। कुछ राज्यों की प्रति व्यक्ति आय इतनी कम है कि इन प्रदेशों के लिए देश की प्रगति का कोई अर्थ नहीं है।

जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण किया, उनकी समृद्धि भी बढ़ी। दिल्ली में “टोटल फर्टिलिटी रेट” केवल 1.9 है जबकि यही बिहार में 2.9 और उत्तर प्रदेश में 2.6 है। उल्लेखनीय है कि टी एफ आर 2.1 होने पर जनसंख्या स्थिर हो जाती है। जनसंख्या तेजी से बढ़ाने वाले राज्यों का प्रतिनिधिक संसद में परिसीमन के पश्चात अधिक हो सकता है, क्योंकि यह संख्या जनसंख्या पर आधारित होती है। यदि यही क्रम चलता रहा, तो शीघ्र ही किसी भी राजनीतिक दल के लिए केवल उत्तर भारत के राज्यों के समर्थन के आधार पर ही बहुमत प्राप्त करके देश की सरकार बनाना संभव हो जाएगा। यह एक प्रजाय से उन राज्यों को सजा देने जैसा होगा जिन्होंने तेजी से प्रगति की तथा शिक्षा और स्वास्थ्य पर अच्छा काम किया। क्या सरकार इस सच्चाई को स्वीकार कर सकती है कि देश में असमानता पहले से कहीं अधिक बढ़ी है? न केवल यह, देश की संपत्ति का केंद्रीकरण कुछ ही में परिवारों में सीमित होकर रह गया है। देश के 1 प्रतिशत लोगों के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 40 प्रतिशत है जबकि निचले 50 प्रतिशत के पास कुल 3 प्रतिशत है। यह प्रतिशत पहले से और घटता जा रहा है। अमीर और अधिक अमीर होते जा रहे हैं तथा गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। यह बात कभी भी सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं की जाती। केवल यह बताया जाता है कि कितनी जगह मेट्रो बन गई, चमकमाते स्टेडियम औय वुलेट ट्रेन बना दी गई।

यदि हम 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं और वास्तव में विश्व गुरु कहलाने के अधिकारी बनना चाहते हैं तो वर्तमान सच्चाई को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है।

वर्ल्ड हैपीनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति 116 नंबर पर है। प्रेस की स्वतंत्रता के सूचकांक पर 151 नंबर पर है तथा “करप्शन परसेप्शन इंडेक्स” में भारत की स्थिति 96 नंबर पर है। इन स्थितियों के रहते हुए यह संभव नहीं है

यदि हम 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं और वास्तव में विश्व गुरु कहलाने के अधिकारी बनना चाहते हैं तो वर्तमान सच्चाई को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। वर्ल्ड हैपीनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति 116 नंबर पर है। प्रेस की स्वतंत्रता के सूचकांक पर 151 नंबर पर है तथा “करप्शन परसेप्शन इंडेक्स” में भारत की स्थिति 96 नंबर पर है। इन स्थितियों के रहते हुए यह संभव नहीं है कि हम विकसित भारत या विश्व गुरु का तमगा लेकर घूमते रहें।

या 150 करोड़? सब कुछ केवल अनुमान पर आधारित है। किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। किसी भी देश के लिए जगणगणा ही योजनाएं बनाने का आधार होती है। यह देश के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का विवरण स्पष्ट करती है। सरकार क्यों लगातार जगणगणा करने से अब तक बचती रही है? यह सरकार आंकड़ों की सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती करना जब कोविड में चुनाव कराए जा सकते हैं तो जगणगणा क्यों नहीं?

आंकड़ों के पीछे के सच को स्वीकार करना ही सुधार का रास्ता हो सकता है। यह वैसा ही है जैसे दरी के नीचे की गंदगी को नहीं देखने से सफाई नहीं हो जाती। सरकार को स्वीकार करना जब से बचने की प्रवृत्ति देश के हित में नहीं है, न यह देश की योजना बनाने के लिए सही है। सरकार के पास जब तक वास्तविक आंकड़े ही नहीं होंगे तब तक यह कैसे तय होगा कि कहां कितने विद्यालय, अस्पताल या परिवहन के साधन चाहियें और कितने लोगों को नौकरी चाहिए? बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ रही है और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में सफल नहीं हो पा रही है।

यह भी कहा जा रहा है कि सरकार जगणगणा के आंकड़ों को भी तोडमरोड कर इबुट्टा करना चाह रही है। प्रणकों को यह कहा जा रहा है कि वे परिवार के पास शौचालय होना मान लें, यदि शौचालय बना हुआ है, चाहे वह काम में नहीं आ रहा हो। इसी प्रकार कोई परिवार यदि पडोस के किसी शौचालय अथवा किसी सार्वजनिक शौचालय का उपयोग कर रहा है, तब भी यह माना जाएगा कि परिवार के पास शौचालय है। इस प्रकार से गलत आंकड़े इकट्ठे करके जो योजना बनेंगी, उस पर हमेशा प्रश्न चिन्ह ही लगा रहेगा।

आंकड़ों को बारीकी से जब तक नहीं देखा जाएगा, तब तक असली स्थिति सामने नहीं आएगी। सरकार ने पहले यह कहा था कि 100 प्रतिशत गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं, तो वास्तविकता यह थी कि उस समय भी देश में 3.30 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास विद्युत कनेक्शन नहीं था। जब तक घर के अंदर बिजली का कनेक्शन नहीं हो तब तक गांव के विद्युतीकृत होने का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार जब तक स्वयं के परिवार में उपयोग में आने योग्य शौचालय नहीं हो तब तक परिवार को शौचालय वाले परिवार की श्रेणी में रखना सही नहीं होगा।

शिक्षा और स्वास्थ्य के आंकड़ों की भी लगभग यही स्थिति है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग सभी बालक–बालिकाएं विद्यालय में नामांकित हैं। नामांकित होने से कोई बच्चा शिक्षित नहीं हो जाता, यह बात सरकार के अधिकारियों को पता है लेकिन आंकड़ों के पीछे की सच्चाई को मानना नहीं चाहते। आज भी 4.74 करोड़ बच्चे शिक्षा के आलोक से वंचित हो रहे हैं। इसी प्रकार लाखों व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित होने के कारण कुपोषित भी हो रहे हैं तथा मौत का शिकार भी हो रहे हैं।

कुछ वर्षों पहले नेशनल सैपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन के मुखिया को केवल इसलिए हटा दिया गया था कि उन्होंने सरकार के लिए असुविधाजनक आंकड़े सार्वजनिक कर दिए थे। क्या आंकड़ों को रोकने से या उसके पीछे की सच्चाई को स्वीकार नहीं करने से वास्तविकता बदल जाएगी? आवश्यकता इस बात की है कि सच्चाई से घबराने और उससे दूर भागने के बजाय उनका सामना किया जाए और तत्तुसार योजना बनाई जाए ताकि जो कमी है, उसको दूर करने के लिए ठोस प्रयास किए जा सकें। जब उन कमियों को स्वीकार ही नहीं किया जाएगा तो फिर उनको दूर करने के लिए प्रयास करने की बात तो दूर की है।यदि इसी प्रकार से सरकार सच को स्वीकार करने से बचती रही और आंकड़े सार्वजनिक करने से भी बचती रही तो वह सही दिशा में योजनाएं बनाने का काम नहीं कर सकती।

बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संवैक्षणों को सरकार, भारत के विरुद्ध साजिश बता कर उन आंकड़ों को नकारने का प्रयास करती है। होना तो यह चाहिए कि यदि सरकार को ये आंकड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं तो अपने आंकड़े एकत्र करें और उन्हें सार्वजनिक करें ताकि लोग पता कर सकें कि सरकार के आंकड़े कितने सही हैं? सरकार ऐसा करना नहीं चाहती, यही तो समस्या है।

आशा की जानी चाहिए कि जगणगणा में लगे प्रणकों को ईमानदारी से वास्तविक स्थिति पता करने के लिए कहा जाएगा न कि बनावटी आंकड़े एकत्र करने के लिए।

ऐसा होने के बाद ही सरकार देशवासियों के लिए सही प्रकार की योजनाएं बनाने में सक्षम हो पाएगी। तब, शायद असमानता को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा और भारत की प्रतिष्ठा अंतरराष्ट्रीय जगत में बढ़ाने की दिशा में सही कदम उठाए जा सकेंगे। कुल मिलाकर, आवश्यकता इसी बात की है कि सरकार सच्चाई का सामना करने का साहस करे। यही उसके और देशवासियों के हित में है।

—अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



अनुराग शुक्ला

बंगाल में टीएमसी की हार ने कांग्रेस का हौसला बढ़ा दिया है। कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के भीतर अपनी स्थिति को फिर से परिभाषित करने का प्रयास कर रही है।

“**कह कबीर कैसे निभे बेर-केर के संग**

वे डोलत मन आपने, उनके फाटत अंग”।

वैसे तो कबीरदास जी ने कई सौ साल पहले एक ऐसी बात लिखी थी जो शत प्रतिशत सही है पर राजनीति में सोलह आने सच्ची बात भी हमेशा पूरी तरह सच नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ भी आने को तैयार है पर सियासी तौर पर एक–दूसरे

को तौल भी रहे है। गठबंधन की तरफ जाते भी दिख रहे हैं और रास्ते में दोनों पाटियों के बयानों के स्पीड ब्रेकर भी कई सारे हैं।

हाल में ये ही बात तब और बढ़ी जब उत्तर प्रदेश के नए नए प्रभारी बने राजेंद्र पाल गौतम ने लखनऊ आते ही सियासी बयान का गोला दाग दिया। उन्होंने हिस्सेदारी बराबरी की होने की बात की। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने उनके बयान को राजनीतिक पहचान बनाने कोशिश कहकर अनसुना कर दिया। वैसे राजेंद्र पाल गौतम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, उनकी सियासत के कई पहलू हैं। राजेंद्र गौतम वो नेता हैं जो बिना किसी पूर्व सूचना के सांसद तनुज पुनिया के साथ मायावती के घर उनसे मिलने पहुंचे थे। हालांकि मायावती ने उन्हें मिलने नहीं दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। उस दौरान भी चर्चा उड़ी थी कि राजेंद्र और तनुज गठबंधन का प्रस्ताव लेकर मायावती के पास पहुंचे थे। अब राजेंद्र गौतम को ही यूपी का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है।

पहले कारण बताओ नोटिस और कुछ ही दिन में यूपी जैसे सबसे महत्वपूर्ण राज्य का प्रभारी बनना संकेत दे रहा है कि गौतम का ये बयान सिर्फ सुर्खियों में रहने की कवायद भर नहीं है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस ने बराबरी का हक मांगा है। इससे पहले कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद सभी सीटों पर तैयारी और बराबरी की बात कर चुके हैं। उन्होंने तल्लू अंदाज में कहा था हम समाजवादी पार्टी से भीख नहीं मांगते हैं कि वे हमें कितनी सीट देंगे, बराबरी पर बात होगी। समाजवादी पार्टी कौन है हमें सीट देने वाली, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कांठोस की तैयारी पूरी है। पश्चिम बंगाल में ममता के साथ जो हुआ उसकी सीख सबको लेनी चाहिए। दअसल बंगाल में टीएमसी की हार ने कांग्रेस का हौसला बढ़ा दिया है। कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के भीतर अपनी स्थिति को फिर से परिभाषित करने का प्रयास कर रही है। सीटों के समान बंटवारे की सार्वजनिक घोषणा करके वह संकेत दे रही है कि वह अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक जूनियर पार्टनर के तौर पर अपनी पहचान बदलना चाहती है। पार्टी लोकसभा चुनावों के बाद संगठन को मजबूत बना रही है और बराबरी का दर्जा मांग रही है वैसे भी यूपी कांग्रेस का गढ़ रहा है।

ये बात और है कि आज उसके पास सियासी जमीन नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि वो 170 सीटों तक की मांग कर सकती है जबकि सपा 60–80 सीटें देने का मन बना रही है। सपा के पास पीडीए का समीकरण और संगठन की ताकत है तो कांग्रेस ग्रांड ओल्ड पार्ट का

भक्ति संगीत के शिखर पुरुष भजन गायक “रामचंद्र गोयल”



मिश्रीलाल पंवार

भक्ति संगीत की दुनिया में उच्च कोटि के गायक के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले जोधपुर के भजन गायक रामचंद्र गोयल आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। देश के महान भजन गायकों में उनकी एक अलग ही पहचान है। बचपन में वे अपनी माता जी को पूजा पाठ के दौरान भजन गाते देखते तो बाल मन सोचता, काश वे भी इतना अच्छा गा पाते। शायद माता जी की इसी विरासत के चलते उन्होंने आगे चलकर इनका ऊंचा मुकाम हासिल किया। उन्होंने सबसे पहले स्कूल में भजन गायन शुरू किया। बाद में कड़ी मेहनत तथा साधना से उन्होंने देश के उच्च कोटि के भजन गायकों में अपना स्थान बना लिया।

जोधपुर के पावटा, पोलो में रहने वाले श्री रामचन्द्र गोयल का जन्म जोधपुर से करीब चालीस किलोमीटर दूर मथानियाँ गाँव में 02 नवम्बर 1936 को पीपा क्षत्रिय समाज के एक साधारण परिवार में हुआ। पिताजी सिलाई का काम करते थे। छह भाई–बहानो में वे सबसे छोटे थे। बाल्यावस्था की छोटी उम्र में ही माँ के द्वारा आराधना स्वरूप सुबह–शाम

गाये जाने वाले भजनों को सुनते तो भाव विभोर हो जाते। मन करता, काश वे भी इतना सुरीला भजन गा पाते। माँ के कारण बचपन से ही भजन के प्रति गहरा लगाव हो गया। धीरे–धीरे गाँव की स्कूल में भजन गाने शुरू किए। लोगों से सराहना मिली तो भजन के प्रति लगाव बढ़ता ही गया। अपनी प्रारम्भिक शिक्षा गाँव में पूरी करने के बाद जोधपुर में आ गए। सम्पूर्ण शिक्षा पूरी कर गृहस्थी चलाने के लिए बिजली विभाग में बाबू की नौकरी कर ली। इसके साथ ही सुबह–शाम भक्ति संगीत की साधना में लगे रहे। भारतीय संगीत के पंडित हुकमदास जी व वी.एन.क्षीरसागर जी से संगीत की शिक्षा प्राप्त कर संगीत विषाद की डिग्री ली। तड़के चार बजे उठ कर संगीत की साधना में जुट जाते।

धीरे–धीरे भक्ति संगीत के क्षेत्र में इन्होंने अपनी अलग ही पहचान बना ली। जब वे मंच से भजनों की सरिता बहाते तो सुनने वाले झूम उठते। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते। अपनी माताजी के बाद उल्हासनगर (बंबई) की पूज्य माताजी हरवंश नाँगिया के सान्निध्य एवं प्रेरणा से आपके मन में संगीत एवं भजनों के प्रति गहरी रुचि जागृत हुई, जिसने आगे चलकर आपके जीवन को पूर्णत: भक्ति संगीत की साधना के मार्ग पर अग्रसर किया।

राजीव गांधी के निधन के बाद उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर दिल्ली में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में इनका भक्ति संगीत का कार्यक्रम रखा गया। इस भक्ति संगीत कार्यक्रम में कई केन्द्रीय मंत्री तथा प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ देश की सभी प्रमुख हस्तियाँ मौजूद थीं। उस दिन उन्होंने जोधपुर का जो मान बढ़ाया, उसकी धमक आज भी दिल्ली की फिजाओं में

तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने मामले की गंभीरता को समझा और कार्रवाई करते हुए सभी प्रक्रिया पूरी की और भूमि के खता विभाजन और भूमि के स्पष्ट बंटवारे के लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे।ग्राम पंचायत घाट का बराना में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में दोनों किसान अपनी समस्या लेकर पहुंचे। मौके पर मौजूद

लेबल लेकर चल रही है। मायावती के घर जाने की कोशिश कर कांग्रेस ने संदेश दे दिया है कि यूपी में सिर्फ सपा के भरोसे नहीं है।

सपा को पता है कि कांग्रेस के नेता चाहे जो बोल लें आखिरी फैसला हाईकमान लेगा। इसलिए अखिलेश ने चुपी साध ली है। उन्हें पता है कि बातचीत की टेबल पर आंकड़े उनके पक्ष में हैं। कांग्रेस यूपी में 37 साल से सत्ता में नहीं है। हर चुनाव में उसकी हालत पतली ही होती गयी है। यूपी में 1989 में कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई तो 425 सीटों में से सिर्फ 94 सीटें ही जीत पाई। फिर 1991 में 419 में से सिर्फ 46, 1993 में 422 में से सिर्फ 28, 1996 में 424 में से सिर्फ 33, 2002 में 403 में से सिर्फ 25, 2007 में 403 में से सिर्फ 22, 2012 में 403 में सिर्फ 28, 2017 में 403 में सिर्फ सात और 2022 में 403 में से सिर्फ दो सीटें ही जीत सकी है। वो भी ऐसी जो नेताओं ने व्यक्तिगत तौर पर जीती थीं। ऐसे में अखिलेश चुप है बेवजह के बयान नहीं देना चाहता। सीट की जगह जित्ताऊ प्रत्याशी की बात करते हैं।

यूपी में कांग्रेस के अच्छे दिनों में उसकी दलित, पिछड़ा और ब्राह्मणों का सपोर्ट था पर ये कहानी पुरानी है। नई कहानी है कि पिछड़ा और दलित वोटों ने अखिलेश की विस्तार चाहते हैं तभी तो पीडीए की राजनीति कर रहे हैं। वहीं

कांग्रेस को भी अपने परंपरागत दलित वोटर तक पहुंचना है। कांग्रेस का विस्तार सपा के वोटों के मूल्य पर होगा। पर इस समय सपा को चिंता वोट की नहीं 10 साल से सत्ता में बैठी भाजपा की है। इससे भी बढ़कर यूपी में 2024 की सफलता को अगर सपा दोहराती है तो इंडी गठबंधन में अखिलेश का रुतबा बढ़ेगा, कद बढ़ेगा। ये बात कांग्रेस को भी पता है। राहुल गांधी आम तौर पर अपने से बड़ा किसी और का सियासी कद बढ़ाश्त नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि बराबरी के बंटवारे की बात हो रही है।

सपा गठबंधन तोड़ना नहीं चाहती, ऐसे में ये भी हो सकता है कि सपा 80 सीटें कांग्रेस को दे और 20–30 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी अपने सिंबल पर उतार दे। अखिलेश जो ये फार्मूला बहुत भाता है। सपा संयमित है क्योंकि उसकी लड़ाई अभी भाजपा से है, कांग्रेस व्याकुल है क्योंकि उसको यूपी की सियासी जमीन चाहिए। अभी ये तो तय माना जा रहा है कि दोनों पार्टियां मिलकर ही चुनाव मे ताल ठोकेंगी पर दोनों को पता है कि–

मिले हैं हाथ तो अब साथ चलना लाज़मी है, मगर यहाँ कोई भी समझौता मुफ्त का नहीं होता।

—अनुराग शुक्ला, (लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

	
रामचंद्र गोयल	
	
अपने भजनों व रामचरित मानस को स्वर दिया। स्वामी जी के अलावा देश के नामी-गिरामी जी के वचना व भजन गायकों से गहरा सम्पर्क रहा जिनमें ईश्वरानंद जी, सत्यमित्रानंद जी, अभयगाम जी महाराज प्रमुख हैं।	
राष्ट्रदूत संवाददाता से बातचीत करते रामचन्द्र गोयल कहते हैं उन पर सर्वाधिक प्रभाव संतों के जीवन से पड़ा है। प्रोत्साहन के बारे में पूछने पर कहते हैं कि भगवान का प्रोत्साहन ही मुख्य रूप से रहा। रामचंद्र गोयल अपनी समस्त उपलब्धियों का श्रेय अपने आराध्य भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी तथा अपनी माँ एवं स्वामी रामसुखदास जी महाराज की असीम कृपा को देते हैं। उनका मानना है कि इन्हीं की कृपा से उनका मानव जीवन सफल हुआ। नब्बे वर्ष की उम्र में भी पढ़ने की आदत नहीं छोड़ी है। आज भी वे स्वाध्याय करते हैं। गोयल खुद भजन लिखते भी हैं। अब तक करीब सौ भजन लिख चुके हैं।	
—मिश्रीलाल पंवार, लेखक जोधपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं।	

ग्रामीण सेवा शिविर में लोगों की मिल रही राहत

बूंदी, (निर्सं)। आमजन को राहत पहुंचाने की दिशा में शुरू किए गए ग्रामीण सेवा शिविरों से ग्रामीणों के रितैर राहत मिल रही है। ग्राम पंचायत घाट का बराना में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में दो किसानों की कृषि भूमि के बंटवारे का वृत्त पुराना मामला मौके पर ही हल कर दिया गया। ग्राम बलदेवपुरा निवासी किसान ओमप्रकाश

और मानसिंह अपनी 1.73 हेक्टेयर कृषि भूमि के खता विभाजन को लेकर काफी समय से परेशान थे। राजस्व रिकार्ड में नाम दफ्त करवाने और भूमि के स्पष्ट बंटवारे के लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे।ग्राम पंचायत घाट का बराना में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में दोनों किसान अपनी समस्या लेकर पहुंचे। मौके पर मौजूद

तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने मामले की गंभीरता को समझा और कार्रवाई करते हुए सभी प्रक्रिया पूरी की और भूमि के खता विभाजन और भूमि के स्पष्ट बंटवारे के लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे।ग्राम पंचायत घाट का बराना में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में दोनों किसान अपनी समस्या लेकर पहुंचे। मौके पर मौजूद

	
राशिफल मंगलवार 14 जुलाई, 2026	
	
आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, मंगलवार, विक्रम संवत 2083, पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 12:10 तक, व्याघात योग दिन 11:57 तक, नाग करण दिन 3:14 तक, चन्द्रमा आज सायं 6:49 से कर्क राशि में संचार करेगा।	
ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-वृष, बुध-मिथुन, गुरू-कर्क, शुक्र-सिंह, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह	
आज कुमार योग दिन 3:14 से रात्रि 12:10 तक है। आज आषाढ़ी अमावस्या, देवपितृकार्य अमावस्या और सोमवती अमावस्या है।	
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:09 से 10:51 तक, लाभ-अमृत 10:51 से 2:14 तक, शुभ 3:56 से 5:38 तक। राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 5:46, सूर्यास्त 7:19	

	
मेघ	
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। नये-पुनये मित्रों से मुलाकात हो सकती है। परिवजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।	

	
वृष	
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से संपन्न हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।	

	
मिथुन	
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।	

	
कर्क	
व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि हो सकती है। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता से मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यक्तिगत कारणों से मन में असंतोष कायम रहेगा।	

	
सिंह	
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित उचित सफलता मिल सकती है।	

	
कन्या	
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। चलते कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों के अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।	

	
तुला	
धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। धार्मिक स्थलों की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। व्यावसायिक अड़चनें दूर होंगे लगेगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा।	

	
वृश्चिक	
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है।शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।	

	
धनु	
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक संर्षक बनेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	

	
मकर	
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी।शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकती है। धार्मिक कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।	

	
कुंभ	
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	

	
मीन	
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। आज परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	

अजमेर जेएलएन में किसान की मौत, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया

परिजनों का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने उनकी जांच रिपोर्ट किसी अन्य महिला मरीज की रिपोर्ट से बदल दी, जिसके आधार पर कई घंटों तक गलत उपचार किया गया

- वहीं आरोप है कि मरीज की गंभीर स्थिति बनने के बाद समय पर ऑक्सीजन, ट्रॉली और गहन चिकित्सा इकाई की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे मरीज की जान चली गई**

- परिजनों ने कोतवाली थाने में शिकायत देकर पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की**

अजमेर, (निसं)। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) चिकित्सालय में इलाज के दौरान गंभीर लापरवाही का आरोप सामने आया है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा निवासी 66 वर्षीय किसान भंवरलाल की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने उनकी जांच रिपोर्ट किसी अन्य महिला मरीज की रिपोर्ट से बदल दी, जिसके आधार पर कई घंटों तक गलत उपचार किया गया। इसके साथ ही मरीज की गंभीर स्थिति बनने के बाद समय पर ऑक्सीजन, ट्रॉली और गहन चिकित्सा इकाई की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे मरीज की जान चली गई। मामले को लेकर परिजनों ने कोतवाली थाने में शिकायत देकर पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है।

मृतक के मित्र धनराज ने बताया कि भंवरलाल को पेट संबंधी बीमारी

के चलते 9 जुलाई को महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा से अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया था। दोपहर करीब तीन बजे उन्हें आपातकालीन इकाई में भर्ती किया गया। प्रारंभिक जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें सामान्य वार्ड में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। परिजनों के अनुसार भर्ती होने के बाद पहली रात मरीज की तबीयत में सुधार दिखाई दिया। वे सामान्य बातचीत कर रहे थे और उन्होंने दलिया तथा नारियल पानी भी लिया था। चिकित्सकों ने भी स्थिति सामान्य

बताते हुए उन्हें सामान्य वार्ड में ही रखा। मृतक के पुत्र पप्पू लाल का आरोप है कि अगले दिन नया उपचार शुरू होने के बाद उनके पिता की हालत अचानक बिगड़ने लगी। शाम तक वे परिजनों को पहचान नहीं पा रहे थे, असामान्य व्यवहार करने लगे और रात में दर्द से परेशान होकर बार-बार उठने तथा भागने का प्रयास कर रहे थे। परिजनों ने कई बार ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ को स्थिति से अवगत कराया, लेकिन उनकी शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया।

परिजनों का कहना है कि बाद में

उन्हें जानकारी मिली कि मरीज की जांच रिपोर्ट किसी अन्य महिला मरीज की रिपोर्ट से बदल गई थी और उसी आधार पर उपचार जारी रहा। उनका आरोप है कि इसी वजह से मरीज की हालत लगातार बिगड़ती चली गई।

परिजनों के अनुसार 12 जुलाई की रात मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। उन्होंने तत्काल आईसीयू में भर्ती करने और बलगम साफ कराने की मांग की, लेकिन समय पर कोई व्यवस्था नहीं की गई। मजबूर होकर परिजनों को स्वयं ट्रॉली तलाशनी पड़ी, जिसमें लगभग 20 मिनट का समय लाना पड़ा।

इतना ही नहीं, जब मरीज को

ऑक्सीजन देने का प्रयास किया गया तो लाया गया सिलेंडर खाली निकला। दूसरा सिलेंडर मंगाने और मरीज को आपातकालीन वार्ड से आईसीयू तक पहुंचाने में भी काफी देर हो गई। परिजनों का आरोप है कि यदि समय रहते आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी जाती तो संभवतः मरीज की जान बचाई जा

सकती थी। परिजनों के मुताबिक उपचार में हुई देरी के कारण मरीज ने आईसीयू पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। आईसीयू में ईसीजी जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के पुत्र पप्पू लाल ने कोतवाली थाने में शिकायत देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि एक सामान्य पेट की बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल आए किसान की मौत कथित चिकित्सकीय लापरवाही के कारण हुई है। उन्होंने दोषी चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में अन्य मरीज भी ऐसी घटनाओं का शिकार हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं अस्पताल प्रशासन की ओर से इस संबंध में विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

जोधपुर में हिस्ट्रीशीटर के साथ मिलकर किसान परिवार पर हमला किया

जोधपुर, (कासं)। शहर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में बासनी बेदा की ढाणी मानपुरा में एक किसान परिवार पर हिस्ट्रीशीटर सहित कुछ लोगों ने हथियारों से लैसे होकर जानलेवा हमला कर दिया। हस्त में वुद्ध बुरी तरह घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए एमडीएमडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावर भागते से समय अपनी बाइक और हथियार मौके पर ही छोड़कर निकल गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच आरंभ की है। आरोपियों ने भागते समय जान की धमकी भी दी।

एयरपोर्ट थाना पुलिस ने बताया

कि बासनी बेदा की ढाणी मानपुरा निवासी गोपाल प्रजापत को तरफ से मामला दर्ज कारया गया है। इसमें बताया कि उसके पिता विरमाराम पुत्र फूसाराम रविवार को शाम को अपने खेत में बाढ़ कर रहे थे। तब करीब शाम 6 बजे वहां पर मानपुरा निवासी खिंवरराज पुत्र किशनाराम, गणपत पुत्र यासीराम, गुलाब पुत्र बालुराम तीनों आए और पिता से गाली-गलौच कर मारपीट करनी शुरू कर दी। आरोप है कि उन लोगों ने धारदार हथियार कुल्हाड़ी, कूट और लाठी से हमला किया, जिससे उसके पिता के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। सिर में भी गम्भीर चोट

आयी। परिवार की महिलाओं ने जब बीच-बचाव करना चाहा तो उनसे भी मारपीट की गई। आरोपी हथियार और मोटरसाइकिल वहीं पर छोड़कर भाग गए। मारपीट और हमले में घायल उसके पिता को बाद में एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी भागते समय पुलिस कार्रवाई नहीं करने की धमकी देकर गए। रिपोर्ट में बताया कि आरोपियों में गणपत नाम का शख्स हिस्ट्रीशीटर है जिसके खिलाफ पहले से ही कई प्रकरण दर्ज हैं। फिलहाल एयरपोर्ट थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घायल का अस्पताल में उपचार जारी है।

हथियार बरामद

झुंझुनूं, (निसं)। शहर में हाल ही में हुई डकैती की वारदात की जांच के दौरान कोवाली थाना पुलिस ने एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर अवैध देशी कट्टा बरामद किया है। बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत नया मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार शहर में गत दिनों हुई डकैती के मामले में गिरफ्तार आरिफ पुत्र सरताज कुरैशी से पूछताछ के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी मिली। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस टीम ने नेशनल हाईवे स्थित सिटी कॉलोनी के पास अंसारी कॉलोनी जाने वाले मार्ग पर एक खाली प्लॉट में छिपाकर रखा गया अवैध देशी कट्टा बरामद कर जब्त कर लिया।

हाईवे पर कार अनियंत्रित होकर पलटी, दो जनों की मौत, दो घायल

- चारों दोस्त खाना खाने के लिये निकले थे और वापस कोटा लौटते समय हादसा हो गया**

कोटा, (निसं)। नान्ता थाना इलाके में रविवार देर रात्रि को कोटा-उदयपुर नेशनल हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। हादसे में कार में सवार दो जनों की मौत हो गई एवं दो जने घायल हो गये।

जानकारी के अनुसार चार मित्र कार से कोटा आते समय कोटा-उदयपुर हाईवे हैगिंग ब्रिज के समीप अचानक से भैसों का झुंड आने से तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई, हादसा इतना भीषण था कि कार डिवाइंडर पर चढ़ गई और काफी दूर तक दौड़ती चली गई। हादसे में चारों मित्र क्षतिग्रस्त कार के

भीतर फंस गये। मामले में सामने आया कि चारों दोस्त खाना खाने के लिये निकले थे और वापस कोटा लौटते समय हादसा हो गया। राहगीरों ने जब कार को क्षतिग्रस्त हालत में और चार जनों को कार में देखा तो इसकी सूचना पुलिस व एम्बुलेंस को दी, सूचना पाकर पुलिस

टीम मौके पर पहुंची। नान्ता थाने के सब इंस्पेक्टर चर्मडी लाल ने बताया कि पुलिस को हादसे की सूचना मिली जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि चारों मित्र घर से खाना खाने के लिये कार से कोटा-उदयपुर हाईवे पर निकले थे। रविवार देर रात्रि को वापस कोटा आते समय हैगिंग ब्रिज से पहले तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइंडर पर चढ़ गई और पलटी खा गई। एसआई ने बताया कि हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और चारों युवक उसमें फंस गए, चारों को उपचार के लिये एम्बुलेंस के जरिये अस्पताल

पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद दो जनों को मृत घोषित कर दिया।

एसआई ने बताया कि हादसे में विज्ञान नगर निवासी अमन (27), दादाबाड़ी निवासी कुंतेश वर्मा (32) की मौत हो गई एवं कार में सवार बसंत बिहार निवासी जगदीश जुमरानी (36) व बोरखेड़ा निवासी दीपेश (36) घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसआई ने बताया कि दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है, मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

श्रीडूंगरगढ़ में बेटे ने बुजुर्ग मां की लाठी से पीटकर हत्या की

बीकानेर, (निसं)। बेटे ने बुजुर्ग मां की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। रात को अपनी पत्नी को जगाकर कहा कि मां मर चुकी है। पत्नी ने चिल्लाकर अन्य परिजनों को उठाया। सभी लोग घर के बाहर सो रही 70 साल की बुजुर्ग मां के पास वीड़कर पहुंचे। भाई को देखते ही आरोपी घर से फरार हो गया।

मामला श्रीडूंगरगढ़ थाना इलाके के बाना गांव का रविवार सुबह 4 बजे का है। पुलिस ने आरोपी बेटे रामनिवास को डिटैन कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घटना की जांचकारी ली और बेटे को डिटैन किया है। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घटना की जानकारी ली और बेटे को

- पत्नी को जगाकर बोला मां मर गई, भाई को देखते ही घर से भागा**

- पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घटना की जानकारी ली और बेटे को डिटैन किया**

डिटैन किया है। श्रीडूंगरगढ़ थानाधिकारी कश्यप सिंह राघव ने बताया कि बाना गांव में गीता देवी (70) की हत्या के आरोप में बेटे रामनिवास को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। रामनिवास

के भाई ओमप्रकाश ने पुलिस को बताया कि देर रात 2 बजे रामनिवास घर में ही इधर-उधर उहल रहा था। उस समय उसकी पत्नी भी जाग रही थी। इसके बाद 4 बजे उसने अपनी पत्नी को उठाया और उससे कहा कि मां मर चुकी है। ये सुनकर उसकी पत्नी चिल्लाई और परिजन भी उठ गए। ओमप्रकाश ने बताया कि घर के सभी लोग जागे और बाहर सो रही मां की ओर दौड़े। रामनिवास मां के पलंग को सरका रहा था। सामने मुझे देखकर वह भाग गया। उसने नींद से उठाकर मां की हत्या की है। पुलिस ने बताया कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है। हालांकि उसे हिरासत में लेकर मामले की पूछताछ की जा रही है।

लापता युवती का शव खेत के कुएं में मिला

रामगंजमंडी, (निसं)। कोटा जिले के मोड़क थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह तेलियाखेड़ी स्थित खेत के एक कुएं में अहीर समाज की लापता युवती आरती (26) पुत्री दुर्गालाल का शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक घनश्याम मीणा सहित मोड़क थाना पुलिस

मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए मोड़क अस्पताल पहुंचाया। युवती के परिजनों ने 11 जुलाई को उसके लापता होने पर मोड़क थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद से पुलिस और परिजन उसकी

तलाश में जुटे हुए थे। सोमवार सुबह खेत के कुएं में शव मिलने से क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस ने थाना मोड़क में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा।

विराटनगर के जैन नसिया में छह अष्टधातु की मूर्तियां और चांदी के छत्र चोरी

पावटा, (निसं)। विराटनगर कस्बे के किला-कोटवाली रोड स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन नसिया में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर मंदिर का ताला तोड़कर 6 अष्टधातु की मूर्तियां, 1० चांदी के छत्र और अन्य

- घटना के बाद जैन समाज में रोष, पुलिस प्रशासन से जल्द खुलासा करने की मांग की**

- सूचना पर विराटनगर पुलिस, एमओबी और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए**

धार्मिक सामान चोरी कर फरार हो गए। घटना के बाद जैन समाज में भारी रोष व्याप्त है और समाज ने पुलिस प्रशासन



विराटनगर का पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जहां चोरी हुई।

से जल्द खुलासा करने की मांग की है। जैन नसिया समिति के अध्यक्ष संतोष जैन ने बताया कि रविवार, 12

जुलाई की रात करीब 11 बजे मंदिर का मुख्य गेट बंद कर सभी लोग अपने घर चले गए थे। सोमवार सुबह करीब 4

बजे मंदिर खोला गया तो मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो मंदिर में रखे धार्मिक सामान और दानपात्र के आसपास सामान बिखरा पड़ा था तथा कई कीमती धार्मिक वस्तुएं गायब थीं।

सूचना मिलते ही जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। चोरी की सूचना पर विराटनगर पुलिस, एमओबी और एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही संदिग्धों की तलाश में जुट गई है। जैन समाज ने इस घटना को धार्मिक आस्था पर चोट बताते हुए पुलिस प्रशासन से शीघ्र जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी हुए धार्मिक सामान की बरामदगी की मांग की है। वहीं विराटनगर थाना प्रभारी बाबूलाल का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा।

बूंदी, (निसं)। ईसान की सबसे बड़ी जरूरत उसका अपना आशियाना होता है, लेकिन जब उस आशियाने का मालिकाना हक (पट्टा) पाने के लिए

- पट्टा न होने की वजह से राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था**
- लंबे समय तक इंतजार करने के बाद इन परिवार ने पट्टा मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी**

आधी सदी यानी 50 साल गुजर जाए तो उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं। हिंडोली उपखंड क्षेत्र के ग्रामा गांव के घुमंतु/अर्द्ध घुमंतु परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन, राज्य सरकार द्वारा रौशदा ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर ने इनकी दशकों पुरानी मुश्कद पूरी कर दी। जब परिवार को उनके पुश्तैनी मकान का पट्टा सौंपा गया, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।

हरणा निवासी पप्पू नाथ, सुरेश नाथ, अमरनाथ और दिनेश नाथ ने

बताया कि वे पिछले 50 वर्षों से अपने पुश्तैनी मकान के पट्टे का इंतजार कर रहे थे। पट्टा न होने की वजह से वे सरकारी कारगजों में अपने ही घर के



ग्रामीण सेवा शिविर पट्टा तैयार कर परिवार को वितरित किया।

तुरंत संज्ञान लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए हाथों-हाथ पट्टा तैयार कर इन्हें वितरित कर दिया। दशकों पुराना सपना जब हकीकत बनकर उनके हाथों में आया, तो लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। पट्टा पाकर पप्पूनाथ व अन्य सदस्यों ने खुशी जताते हुए कहा कि

जिस काम के लिए उन्होंने आस छोड़ दी थी, वह शिविर में आसानी से पूरा हो गया। राज्य सरकार के इस शिविर ने उनकी उम्मीदों को फिर से ज्वांदा कर दिया है। इस राहत के लिए सभी लाभार्थियों ने राज्य सरकार का आभार जताया।

पेपर लीक के खिलाफ ‘गूँज मैराथन’ में युवा सड़कों पर उतरे

पांच किमी मैराथन में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया

जयपुर। देशव्यापी पेपर लीक की गंभीर समस्या के खिलाफ सोमवार को जयपुर में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा छात्रों की गूँज मैराथन का विशाल आयोजन किया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली की अगुवाई में आयोजित इस मैराथन में हजारों की संख्या में छात्र और युवा सड़कों पर उतरे।

युवाओं के मुद्दों, विशेषकर पेपर लीक के खिलाफ लगातार प्रखर आवाज उठाने वाले जुली ने इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों पर तीखा प्रहार किया। यह दौड़ राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार से शुरू होकर ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल पर संपन्न हुई। इस मैराथन में हजूम उमड़ पड़ा जो इस बात की तस्दीक करता है कि आज युवा नीट समेत देश में भाजपा राज में हो रहे पेपरलीक से बेहद आक्रोशित है।

मैराथन के समापन पर उपस्थित जनसमूह और युवाओं को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने जोश भरते हुए कहा कि इतिहास गवाह है, जब-जब युवाओं ने कुछ तय किया है, तब-तब देश और प्रदेश में बड़ा परिवर्तन आया है। उन्होंने नारा देते हुए कहा, "जब-जब युवा बोला है, राजसिंहासन डोला है।"

जुली ने पेपर लीक के कारण अवसाद में आकर जान गंवाने वाले मासूम छात्रों का मुद्दा उठाते हुए सत्तापक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज सरकार ने अति कर रखी है; देश में 22-22 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, लेकिन भाजपा का एक भी नेता इन पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछने तक नहीं गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश के युवा धर्मरु प्रधान से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग कर रहे थे, पर इस्तीफा तो तब दिया जाए जब



जयपुर में छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा छात्रों की गूँज मैराथन का विशाल आयोजन किया।

- छात्रों की गूँज अभियान के तहत युवाओं ने उठाई पारदर्शी भर्ती परीक्षाओं की मांग
- नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली व एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद जाखड़ मौजूद रहे
- दौड़ राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार से शुरू होकर अल्बर्ट हॉल पर संपन्न हुई

नैतिकता बची हो। इन लोगों की आंखों का पानी पूरी तरह सूख चुका है। टीकाराम जुली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के समय राजस्थान आकर पेपर लीक से मुक्ति के बड़े-बड़े भाषण देने वाले प्रधानमंत्री आज देश के युवाओं की बदहाली पर पूरी तरह मौन हैं। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि मोदी जी के सत्ता में आने के बाद पिछले 12 वर्षों में देश के अलग-अलग हिस्सों में लगभग 90 पेपर लीक हो

चुके हैं, जिसने करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तो ये लोग चंदा चोरी पर उतर आए हैं और भगवान राम के नाम को भी नहीं बख्खा रहे हैं। जुली ने युवाओं का आव्हन करते हुए कहा कि आप ही वो लोग हैं जिन्होंने इन्हें सत्ता की कुर्सियों पर बैठाया था और अब यही जांबाज छात्र और युवा इन्हें सत्ता से उतारने का काम करेंगे। आने वाले समय में इनका सूपड़ा साफ होना तय है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश के

इस विशाल मैराथन और विरोध प्रदर्शन में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, कांग्रेस विधायक मनीष यादव, विधायक शिखा बराला, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी, कोटपुतली-बहरोड़ इंड्राज गुजर, सांगनेर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे पुष्पेंद्र भाट्टाज, हरसहाय यादव, देशराज मीणा, सुमित भगसास, रामसिंह सामोता एवं रोहित जुली सहित कांग्रेस और एनएसयूआई के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, छात्र नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

ज्वैलर पर जानलेवा हमला करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

‘साहित्य को सही दिशा देने की ज़रूरत’

जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) और खोराबीसल थाना पुलिस ने नांगल लाड़ी गांव में ज्वैलर पर जानलेवा हमला कर करीब 10 किलो सोने-चांदी के जेवररात लूटने वाली अंतरजिला गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 25-25 हजार रुपए के दो इनामी बदमाशों समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लूटे गए जेवरतों को गलाकर बनाई गई करीब 7

- लूटे गए जेवर गलाकर बनाई सात किलो चांदी की सिल्ली बरामद
- चोमू से किराये की स्विफ्ट कार लेकर दिया था वारदात को अंजाम

किलोग्राम चांदी की सिल्ली तथा वारदात में प्रयुक्त स्विफ्ट कार बरामद की गई है। वहीं वारदात में शामिल एक आरोपी अब भी फरार है। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।



पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

डीसीपी (पश्चिम) प्रशांत किरण ने बताया कि 3 जुलाई 2026 की रात खोराबीसल थाना क्षेत्र के नांगल लाड़ी गांव स्थित श्याम ज्वैलर्स के संचालक शंकरलाल शर्मा (45) पर उस समय हमला हुआ था, जब वह दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से मुण्डोता रोड स्थित अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में पीछे से आई सफेद स्विफ्ट कार ने उनकी बाइक को ओवरटेक कर रोक लिया। कार से उतरे चार बदमाशों ने लाठी और सरियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बचाव के दौरान शंकरलाल के दोनों हाथ टूट

गए, जबकि सिर, नाक और आंखों पर भी गंभीर चोटें आईं। इसके बाद बदमाश उनके गले में लटका करीब 10 किलो सोने-चांदी के जेवररात और 15 हजार रुपए नकदी से भरा बैग लूटकर मुण्डोता की ओर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह तथा डीएसटी प्रभारी गणेश सेनी के नेतृत्व में चार विशेष टीमों का गठन किया गया। वारदात के समय घना अंधेरा और तेज बारिश होने से पुलिस के पास कोई प्रत्यक्ष सुराग नहीं था।

जयपुर। राही सहयोग संस्था के निदेशक प्रबोध गोविल ने प्रेस विज्ञापित जारी करते हुए बताया कि राही सहयोग संस्थान और राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा सांमिति के संयुक्त तत्वावधान में सुप्रसिद्ध कवि, गीतकार, ग़ज़लकार और गंगा- जमनी तहजीब के संवाहक इकराम राजस्थानी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर विशद चर्चा का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में इकराम राजस्थानी के व्यक्तित्व व कृतित्व से संबंधित चर्चा में भाग लेते हुए सर्वप्रथम गज़लकारा निरुपमा चव्हेदी ने उनके कविता सन्ध्वित रचनाकर्म और व्यक्तित्व की खूबियों पर प्रकाश डाला।

इकराम जी के सुपुत्र वरिष्ठ शिक्षाविद् और गीतकार फ़ीरोज खान ने अपने पिता के साहित्य के साथ-साथ उनके सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों के अनुपालन में संजीवनी और कर्तव्य निष्ठा से परिचित करवाया। प्रसिद्ध उपन्यास कारण प्रेमलता सोनी ने राजस्थानी जी के राजस्थानी भाषा प्रेम और उनकी मायगु भाषा में लिखी रचनाओं व लोकगीतों के बारे में बात की।प्रेमलता सोनी ने साहित्यकार राजेश कमाल के आलेख का वाचन भी किया।

टीबी मुक्त राजस्थान के लिए पंचायतवार प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने टीबी मुक्त राजस्थान के लिए पंचायतवार प्रभावी मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप समाज के हर वर्ग को साथ लेकर, इस बीमारी के प्रति फैले डर और

- राज्यपाल ने ली टीबी उन्मूलन प्रगति की समीक्षा बैठक
- पंचायतवार मॉनिटरिंग और प्रत्येक मरीज पर ध्यान देने के दिए निर्देश

भेदभाव को दूर किया जाए। उन्होंने आंकड़ों में नहीं व्यवहार में प्रत्येक मरीज पर ध्यान देने पर जोर दिया तथा कहा कि टीबी को पूरी तरह से खत्म किया जाए। इसके लिए उन्होंने हर गांव में घर-घर जाने और टीबी मरीजों को वास्तविक रूप में चिन्हित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गांवों में टीबी



राज्यपाल ने टीबी उन्मूलन हेतु जनभागीदारी को और सुदृढ़ करने के लिए समीक्षा बैठक की।

मुक्त करने के प्रयासों हेतु ग्राम समकों को जवाबदेह बनाया जाए।

बागडे सोमवार को लोकभवन में टीबी उन्मूलन हेतु जनभागीदारी को और सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कागज में नहीं वस्तुस्थिति में टीबी रोगियों को रोग मुक्त करने के प्रयास होने चाहिए। उन्होंने टीबी रोगियों के समग्र इलाज और बाद में पोषण पर

भी विशेष ध्यान देने का आव्हान किया। उन्होंने प्रचलित कहावत "खरगोश के शिकार के लिए बाघ के शिकार की तैयारी" का उल्लेख करते हुए कहा कि टीबी मुक्त करने के लिए मन से प्रयास हों। उन्होंने जिला कलेक्टर स्तर पर टीबी मरीजों का पता लगाने और उनके प्रभावी निदान के लिए जागरूकता के आधिकाधिक कार्य किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा

कि मरीज गोद लेकर कार्य किए जाने के आंकड़ों की वास्तविकता का भी पता लगाया जाए। राज्यपाल ने इससे पहले टीबी रोगी परिवार को निक्षय मित्र कीट का वितरण किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गर्जेन्द्र सिंह खोंवसर ने कहा कि सभी विभागों की सहभागिता से राजस्थान को टीबी मुक्त करने के लिए निरंतर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह से की शिष्टाचार भेंट

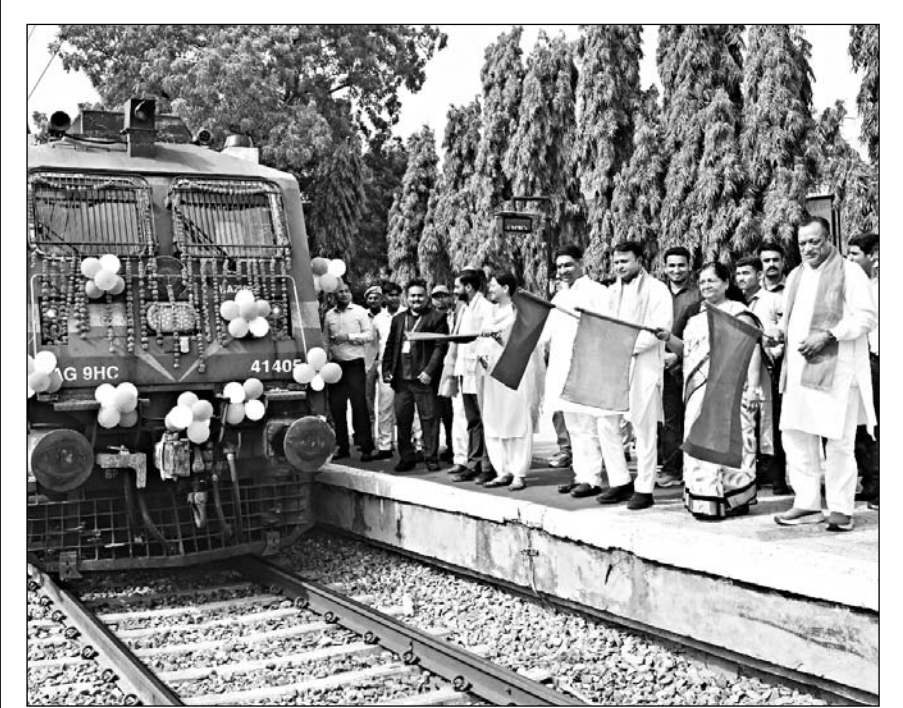
जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोमवार को 9 बार की विधायक, राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष रही सुमित्रा सिंह से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट कर स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पुराने संस्मरणों को भी याद किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह ने भी 2003 से 2008 तक के कार्यकाल में हुए संस्मरणों पर संवाद किया। राठौड़ ने कहा कि सुमित्रा सिंह ने अपने सार्वजनिक जीवन में प्रदेश और समाज की सेवा के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है। सदन में सुमित्रा सिंह अपने कड़क अनुशासन और संसदीय नियमों की गहरी जानकारी के लिए जानी जाती रही। इस दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री डॉ अर्पूा सिंह, भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक, प्रदेश प्रवक्ता स्टेफी चौहान ने भी सुमित्रा सिंह के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना की।

मुख्य सचिव ने अक्षय ऊर्जा आधारित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

- मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के विकास के साथ डिस्कॉम्स की वित्तीय मजबूती सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है

उत्पादित अतिरिक्त बिजली के प्रभावी भंडारण के लिए यह तकनीक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से पीक आवर्स में महंगी बिजली खरीदने की आवश्यकता कम होगी तथा डिस्कॉम्स को प्रतिवर्ष उल्लेखनीय वित्तीय बचत होगी। इसका लाभ आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। बैठक में बताया गया कि जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम के विभिन्न सर्किटों में इन परियोजनाओं के लिए स्थान चिह्नित किए जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने डिस्कॉम्स के ऋण पुनर्गठन की प्रगति की समीक्षा करते हुए

कहा कि आरईसी एवं पीएफसी से लिए गए उच्च ब्याज दर वाले ऋणों की री-प्राइसिंग से डिस्कॉम्स को प्रतिवर्ष उल्लेखनीय ब्याज बचत प्राप्त हो रही है। उन्होंने शेष उच्च ब्याज दर वाले ऋणों की भी शीघ्र री-प्राइसिंग सुनिश्चित करने के लिए संबंधित वित्तीय संस्थाओं के साथ प्रभावी समन्वय एवं वार्ता करने के निर्देश दिए। वी. श्रीनिवास ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज- के अंतर्गत हनुमानगढ़ एवं उदयपुर में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए परियोजनाओं को तय समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से राज्य में अक्षय ऊर्जा के सुगम ट्रांसमिशन को बढ़ावा मिलेगा तथा राजस्थान का ट्रांसमिशन नेटवर्क और अधिक आधुनिक एवं सुदृढ़ बनेगा। मुख्य सचिव ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अधिकाधिक लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी सूचना, शिक्षा एवं संचार आईईसी कार्यक्रमों तैयार कर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।



वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत सोमवार को पहली ट्रेन दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन जयपुर से रवाना हुई। रामेश्वरम-मटुरै के लिए जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

हाईटेक अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के चार आरोपी गिरफ्तार

जयपुर, दिल्ली, गुजरात और उत्तराखंड से चुराते थे स्कॉर्पियो

जयपुर। जयपुर पूर्व जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) और रामनगरिया थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक हाईटेक अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 10-10 हजार रुपए के दो इनामी बदमाशों सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने जयपुर, दिल्ली, गुजरात और उत्तराखंड से दो दर्जन से अधिक स्कॉर्पियो चोरी करना स्वीकार किया है। गिरोह चोरी की गाड़ियों के इंजन और

- सीकर में बदलते थे इंजन-चेसिस नंबर, नेपाल तक जुड़े तार

चेसिस नंबर बदलकर उन्हें बाजार में बेचता था, जबकि कुछ वाहन नेपाल तक सप्लाई किए जाते थे।

डीसीपी (पूर्व) रंजीता शर्मा ने बताया कि रामनगरिया थाना पुलिस और डीएसटी पूर्व ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के मुख्य सरगना राहुल मीणा उर्फ कुंदन उर्फ राजा (26) निवासी समलेटी, महवा (दौसा), उसके सगे भाई हरेतो मीणा उर्फ मोनू उर्फ दुरा (20), चोरी की गाड़ियां खरीदने वाले महिपाल चौधरी (35) निवासी कैलाश नगर, सीकर तथा हिमांशु देहिवाल (20) निवासी कोछेर, जीणमाता



रामनगरिया थाना पुलिस और डीएसटी पूर्व ने 10-10 हजार रुपए के दो इनामी बदमाशों सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया।

(सीकर) को गिरफ्तार किया है। राहुल मीणा पर जयपुर पूर्व और दौसा पुलिस ने 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। वह मध्यप्रदेश के मुरैना और दौसा के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के मामलों में भी फरार चल रहा था।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से रामनगरिया और करधनी थाना क्षेत्र से चोरी की गई दो स्कॉर्पियो, वारदात में प्रयुक्त स्विफ्ट कार , चार एसीएम मशीनें, चार वीसीएम मशीनें, तीन जोड़ी फर्जी नंबर प्लेट तथा पेचकस, पाना, प्लास सहित वाहन चोरी में प्रयुक्त अन्य उपकरण बरामद किए हैं। आरोपी इन

आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से वाहनों के सुरक्षा सिस्टम को बायपास कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे।

पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे पहले विभिन्न शहरों में खड़ी स्कॉर्पियो की रेकी करते थे। चोरी के बाद वाहनों को सीकर ले जाकर गैराज संचालकों को दो से तीन लाख रुपए में बेच देते थे। वहां दुर्रटनाग्रस्त या पुरानी गाड़ियों के इंजन और चेसिस नंबर चोरी की गाड़ियों में फिट कर उनकी पहचान बदल दी जाती थी और बाद में उन्हें ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता था।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरोह ने जयपुर के अलावा दिल्ली, गुजरात और उत्तराखंड से भी दो दर्जन से अधिक स्कॉर्पियो चोरी की है। गुजरात से चोरी किए गए वाहनों को चित्तौड़गढ़ में खपाया जाता था, जबकि दिल्ली और उत्तराखंड से चोरी की गई गाड़ियों को साथी रिकू लालपुर के माध्यम से नेपाल तक सप्लाई किया जाता था।

वहीं मुख्य आरोपी राहुल मीणा के खिलाफ राजस्थान और मध्यप्रदेश के विभिन्न थानों में हत्या, वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

जानलेवा हमले का आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा 10 जुलाई को रात से तबादलों पर प्रतिबंध लागू किए जाने के बावजूद भाजपा में तबादलों को लेकर असंतोष धमता नजर नहीं आ रहा है। सोमवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में तबादला करवाते, निरस्त कराने और संशोधन की मांग को लेकर कर्मचारियों और उनके परिजनों की भारी भीड़ उमड़ी। प्रतिबंध लागू होने के तीन दिन बाद भी भाजपा कार्यालय में तबादलों से जुड़े आवेदन लिए जा रहे और सिफारिशों का सिलसिला जारी रहा।

तबादलों को लेकर पार्टी के भीतर भी नाराजगी खुलकर सामने आई। सूत्रों के अनुसार विधायक जेठानन्द व्यास, बालमुकुंद आचार्य और देवीसिंह शेखावत सहित कई भाजपा विधायक

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा 10 जुलाई को रात से तबादलों पर प्रतिबंध लागू किए जाने के बावजूद भाजपा में तबादलों को लेकर असंतोष धमता नजर नहीं आ रहा है। सोमवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में तबादला करवाते, निरस्त कराने और संशोधन की मांग को लेकर कर्मचारियों और उनके परिजनों की भारी भीड़ उमड़ी। प्रतिबंध लागू होने के तीन दिन बाद भी भाजपा कार्यालय में तबादलों से जुड़े आवेदन लिए जा रहे और सिफारिशों का सिलसिला जारी रहा।

तबादलों को लेकर पार्टी के भीतर भी नाराजगी खुलकर सामने आई। सूत्रों के अनुसार विधायक जेठानन्द व्यास, बालमुकुंद आचार्य और देवीसिंह शेखावत सहित कई भाजपा विधायक

लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। भाजपा मुख्यालय में दिग्भर तबादला चाहने वाले, तबादला निरस्त करवाने वाले और संशोधन की मांग करने वाले कर्मचारियों की लंबी कतारें लगी रही। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी सहित अन्य पदाधिकारी लोगों से आवेदन लेते और उनकी समस्याएं सुनते दिखाई दिए।

जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर कोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली

धमकी भरे ई-मेल के बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता व सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान चलाया

जयपुर/जोधपुर/अजमेर/अलवर , (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर और जयपुर पीठ, अजमेर जिला न्यायालय परिसर, अलवर अदालती परिसर को सोमवार सुबह एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद न्यायिक और प्रशासन में हड़कंप मच गया। धमकी भरा ई-मेल मिलते ही पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां और बम निरोधक दस्ते को सूचना दी गई। धमकी के बाद जोधपुर हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई तथा पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई। जानकारी के अनुसार धमकी किसी अज्ञात ई-मेल आईडी से भेजी गई है। सुरक्षा एजेंसियां ई-मेल के ख़ौत और भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है।

जयपुर में हाईकोर्ट में फिर बम ब्लास्ट की धमकी :- जयपुर मे राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल भेजा गया है। इससे पूर्व अब तक हाईकोर्ट को एक दर्जन बार इस तरह की धमकी भरे ई-मेल मिल चुके हैं। मेल मिलने के बाद हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से पुलिस उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। इस पर दौरान जांच एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर हाईकोर्ट की मुख्य बिल्डिंग की गहनता से जांच की। वहीं बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वांड ने चप्पे-चप्पे की



जयपुर हाई कोर्ट परिसर में पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां और बम निरोधक दस्ते ने जांच की।

तलाशी ली। हाईकोर्ट प्रशासन को रात 12 बजकर 19 मिनट पर भेजे इस मेल में कहा गया कि जनमानस को नुकसान पहुंचाना हमारा इरादा नहीं है, लेकिन इमारत को नुकसान होगा। इसलिए 6 जिलेटिन बम प्लांट किए गए हैं। सुबह प्रशासन की ओर से मेल देखने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को इसकी सूचना दी गई। कोर्ट समय शुरू होने से पहले सुरक्षा एजेंसियों की ओर से तलाशी पूरी करने से न्यायिक कामकाज बाधित नहीं

हुआ। आएदिन धमकी भरा मेल मिलने के बाद भी अब तक इसे भेजने वालों की जानकारी नहीं मिल पाई है। जिसके चलते वकीलों में खासी नाराजगी है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि धमकी भरे ई-मेल की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और सुबह करीब 7:15 बजे सीओ (उत्तर) शिवम जोशी तथा सिविल लाईंस थाना प्रभारी शंभू सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके

अजमेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी :-अजमेर जिला न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सोमवार सुबह पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां में हड़कंप मच गया। जिला न्यायाधीश को मिले धमकी भरे ई-मेल की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और सुबह करीब 7:15 बजे सीओ (उत्तर) शिवम जोशी तथा सिविल लाईंस थाना प्रभारी शंभू सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके

बाद पूरे न्यायालय परिसर की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। जांच पूरी होने के बाद राहत की बात यह रही कि परिसर पूरी तरह सुरक्षित मिला और किसी प्रकार का विस्फोटक नहीं पाया गया।

अब अलवर डीजे कोर्ट को उड़ाने की मिली धमकी :- अलवर में भी सोमवार सुबह अदालती परिसर में धमकी का ई-मेल मिलने से हड़कंप मच गया। यह धमकी कोर्ट की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर तमिल भाषा में भेजे गए एक मेल के जरिए दी गई। मेल में दावा किया गया कि कोर्ट परिसर में 6 जिलेटिन बम लगाए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गईं। सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे जब अदालती कामकाज के लिए ऑफिस खुला, तब कर्मचारियों की नजर इस मेल पर पड़ी। मेल की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अलवर पुलिस अधीक्षक को मामले की सूचना दी गई। धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। ऐतिहासिक महल परिसर स्थित डीजे कोर्ट सहित पूरे अदालती परिसर को खाली करवाकर तलाशी ली गई। करीब दो घंटे तक चली कड़ी जांच के बाद पुलिस को कोई भी संदिग्ध वस्तु या बम नहीं मिला।

कोटा में 59 हजार के जाली नोट बरामद, आरोपी गिरफ्तार

कोटा , (निसं)। ग्रामीण इलाके के बपावर कलां क्षेत्र के बाजार में 100-200 सौ के नकली नोटों को चलाने के प्रयास के दौरान सूचना पर बपावर कलां पुलिस टीम ने 59300 रुपये के नकली नोटों सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि बपावर पुलिस को सूचना मिली कि एक एसपी नम्बर की बाइक पर एक बैग सहित युवक संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि उक्त सूचना पर पुलिस

■ नकली नोटों को बाजार में चलाने की योजना थी

उपअधीक्षक नरेन्द्र जैन के सुपरविजन में थाने के सहायक उप निरीक्षक रामप्रकाश के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गठित टीम ने विशेष कार्ययोजना बनाकर सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचे। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर बपावर कलां के बाजार में नकली नोट खपाने के प्रयास

में संदिग्ध युवक को डिटेन कर उसके बैग की तलाशी ली, तलाशी के दौरान पुलिस टीम ने बैग में से 100 व 200 रुपये के नकली नोट के कुल 59 हजार 300 रुपये बरामद किया। पुलिस टीम ने मौके पर कार्यवाही करते हुए मध्यप्रदेश के थाना गुना पिपरोदा खुर्द निवासी आनंद कुशवाह (38) को गिरफ्तार किया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पृष्ठताड़ में सामने आया कि उसने नकली नोटा इंस्टाग्राम मित्र रवि से 20 हजार नकद के बदले में प्राप्त किये थे, पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है,

परिवार पर लाठी-डंडों से हमला, छह घायल

छबड़ा , (निसं)। शहर की मोती कॉलोनी में रविवार को एक परिवार पर कथित रूप से लाठी-डंडों से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है।

पीड़ित सुरेश कुशवाह ने बताया कि रविवार को अचानक 4 से 5 महिला-पुरुष उनके घर पहुंचे और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट शुरू कर दी। उनके अनुसार हमलावरों ने लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे परिवार के कई सदस्य घायल हो गए। कुशवाह के अनुसार, जब परिवार के अन्य सदस्य

बीच-बचाव के लिए आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने घर के बाहर खड़ी बैन और बाइक में भी तोड़फोड़ की। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गए। पीड़ित का कहना है कि पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। घटना के बाद पीड़ित परिवार छबड़ा थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज करावते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार घायलों का मेडिकल परीक्षण करवाया है।

कॉलेज की छत से गिरा मजदूर

रामगंजमंडी , (निसं)। चेचट कस्बे के नरसिंह जी के बाग में बन रहे निर्माणाधीन सरकारी कॉलेज में सोमवार सुबह एक हादसा हो गया। प्राप्त जानकारी अनुसार कॉलेज निर्माण कार्य में लगे मजदूर कन्हैयालाल पुत्र कालू भील (40) निवासी रावतभाटा रात में निर्माणाधीन भवन की छत पर सो रहे थे। सुबह नौद में अचानक संतुलन बिगड़ने से वह छत से नीचे गिर गया, जिससे उनके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों ने तुरंत 108 एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस की सहायता से घायल कन्हैयालाल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चेचट लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। गंभीर चोट होने के कारण उन्हें तत्काल बेहतर उपचार के लिए झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल रेफर कर दिया गया।

बूंदी की सूरज छतरी व मोरडी की छतरी वापस अपने वैभव में लौटेंगी

बूंदी , (निसं)। रानियों के ख्वाब का आईना रही ऐतिहासिक सूरज छतरी व मोरडी की (मयूर) छतरी वापस अपने वैभव में लौटेंगी। वन विभाग ने दोनों छतरियों के लिए 25 लाख की टेंडर प्रक्रिया जारी की है।

सेव अवर हेरिटेज फाउंडेशन के अरिहंत सिंह ने बताया कि सूरज छतरी पर सदस्यों के साथ मिलकर नापकर एस्टीमेट बनाकर वन विभाग को सौंप दिया है, ताकि छतरी में सही तरीके से

■ वन विभाग ने दोनों छतरियों के लिए 25 लाख की टेंडर प्रक्रिया जारी की है

जीर्णोद्धार के कार्य हो सके। वन विभाग ने वेबसाइट पर टेंडर जारी कर दिए हैं। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होते ही सूरज छतरी व मयूर छतरी पर जीर्णोद्धार के कार्य शुरू होंगे। सूरज छतरी में मूर्ति का चबूतरा छतरी का गुम्बद सहित कई कार्य होंगे। मयूर छतरी पर भी पर्यटक आसानी से पहुंचे इसके लिए सुगम मार्ग बनाया जाएगा। कार्य पूर्ण होने के बाद पर्यटकों के लिए सूर्योदय व सूर्यास्त के पॉइंट बनेंगे जो पर्यटन जो नए आयाम देंगे। बालचन्द पाडा पश्चिम

छबड़ा के कड़ैयाबन स्थित विद्यालय में शिक्षकों की कमी

छबड़ा , (निसं)। कड़ैयाबन स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर सोमवार को छात्रों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज विद्यार्थियों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति करने की

■ नाराज विद्यार्थियों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया

■ विद्यार्थियों ने जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग उठाई

मांग उठाई। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने बताया कि विद्यालय में लंबे समय से शिक्षकों की कमी बनी हुई है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उनका कहना था कि इस संबंध में कई बार विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है। इस दौरान छात्रों ने नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जताई। विरोध प्रदर्शन में ग्रामीण और



छात्रों और ग्रामीणों ने मांगों को लेकर धरना दिया।

अभिभावक भी शामिल हुए। ग्रामीणों का आरोप था कि सूचना दिए जाने के बावजूद कोई जिम्मेदार अधिकारी करीब एक घंटे तक मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई। प्रदर्शन के दौरान स्कूल गेट पर ताला लगाकर करीब एक घंटे तक धरना दिया गया। कार्यरत कार्यवाहक सीबीईओ चंद्रप्रकाश गुप्ता ने बताया कि विद्यालय में कुल 185 विद्यार्थी नामांकित हैं। स्कूल में शिक्षकों के 17 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 6 शिक्षक ही कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि कई

शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिसके कारण यह स्थिति बनी है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था की गई है तथा रिक्त पदों को भरने के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने मांग की है कि विद्यालय में रिक्त पड़े पदों पर शीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति की जाए ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

जोधपुर में अवैध मॉडिफिकेशन वाली 10 बसें सीज़

नियमों की अवहेलना करने पर जुर्माना लगाया

जोधपुर , (कासं)। जोधपुर में अवैध मॉडिफिकेशन वाली लगभगी एवं स्लीपर बसों के विरुद्ध सोमवार को कार्रवाई जारी रही। 10 बसों पर कार्रवाई की गई। नियमों के अनुसार संबंधित बसों को सीज़ किया गया तथा उनके चालान बनाए गए।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के सदस्य सचिव के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश (अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) जोधपुर महानगर दिनेश त्यागी एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश (अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) जोधपुर जिला पूर्ण कुमार शर्मा के निर्देशों की पालना में सुरक्षित परिवहन के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तथा वैधानिक प्रावधानों एवं सरकारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के

उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बॉम्बे मोटर चौराहा, कल्पतरु बस स्टैंड एवं बारहवाँ रोड चौराहा पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा परिवहन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त जांच टीम के साथ औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान अवैध रूप से संचालित तथा अनधिकृत संरचनात्मक बदलाव करने वाली स्लीपर एवं लक्जरी बसों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 10 बसों पर नियमानुसार कार्रवाई की गई तथा उन्हें सीज़ कर चालान बनाए गए। विशेष अभियान के दौरान कुल 10 बसों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान विभिन्न नियमों का उल्लंघन पाए जाने के संबंध में बसों के विरुद्ध नियमानुसार चालान बनाए गए तथा नियमों की अवहेलना करने वाले संचालकों पर

जुर्माना लगाया गया। वहीं जिन बसों में गंभीर अनियमितताएं एवं अनधिकृत संरचनात्मक बदलाव पाए गए, उन्हें मौके पर ही नियमानुसार सीज़ कर दिया गया।

पूरी कार्रवाई को निष्पक्ष एवं प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के लिए न्यायपालिका, पुलिस एवं परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। आमजन से अपील की गई है कि स्लीपर एवं लक्जरी बसों की जांच यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जान-माल की हानि रोकने के उद्देश्य से की जा रही है। इसमें सभी नागरिक सहयोग करें। यदि कोई यात्री किसी ट्रेवल्स एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करवाना चाहता है, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायालय परिसर, जोधपुर महानगर में संपर्क कर स्थायी लोक अदालत में वाद प्रस्तुत कर सकता है।

नीमकाथाना : कॉजेल में व्याख्याताओं के तबादले से छात्रों में आक्रोश

नीमकाथाना , (निसं)। एसएनकेपी कॉलेज में पांच व्याख्याताओं और एक लैब असिस्टेंट के तबादले के विरोध में सोमवार को छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के आान पर विद्यार्थियों ने कॉलेज का मुख्य द्वार बंद कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि पहले से ही कॉलेज में शिक्षकों की भारी कमी है, ऐसे में तबादलों से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर गंभीर असर पड़ेगा।

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि कॉलेज में पीटीआई सहित करीब 20 पद पहले से रिक्त हैं। इसके बावजूद दो दिनों पूर्व पांच व्याख्याताओं और एक

■ एसएनकेपी कॉलेज का गेट बंद कर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया

■ कॉलेज में पीटीआई सहित करीब 20 पद पहले से रिक्त हैं

लैब असिस्टेंट का तबादला कर दिया गया, जिससे शैक्षणिक व्यवस्था और अधिक प्रभावित होगी। एसएफआई के जिला सचिव विक्रम यादव ने कहा कि जब कॉलेज पहले से ही स्टाफ की कमी से जूझ रहा है तो ऐसे समय में शिक्षकों का तबादला करना विद्यार्थियों के

भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सरकार छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रखना चाहती है। प्रदर्शन की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। कॉलेज प्राचार्य संतोष वर्मा ने छात्रों से वार्ता कर उन्हें शांत कराया और उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन समाप्त करते हुए प्रशासन को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया। छात्रों ने चेतावनी दी कि निर्धारित समय में समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

पूर्व एसएफआई नेता एवं अधिवक्ता गोपाल सैनी ने कहा कि

कॉलेज में पहले से ही लगभग 20 पद रिक्त हैं। ऐसे में लगातार तबादले शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज को धर्मशाला नहीं बनने दिया जाएगा। सरकार छात्रों के हितों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने नई शिक्षा नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान व्यवस्था में परीक्षा, प्रवेश और पढ़ाई का पूरा शैक्षणिक कैलेंडर अव्यवस्थित हो गया है, जिसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने रिक्त पदों को शीघ्र भरने तथा स्थानांतरित किए गए शिक्षकों के तबादले पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।

बूंदी शहर के ऐतिहासिक दरवाजे अब पर्यटकों को आकर्षित करेंगे

बूंदी , (निसं)। बूंदी शहर के ऐतिहासिक दरवाजे आने वाले दिनों में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। शहर की प्राचीन धरोहरों को सहेजने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन ऐतिहासिक दरवाजों के संरक्षण व सौंदर्यीकरण का कार्य 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। यह पहल भारतीय सांस्कृतिक निधि (इंटेक) चैप्टर द्वारा की गई है।

भारतीय सांस्कृतिक निधि के केंद्रीय कार्यालय के निर्देशन में 14 जुलाई की सुबह इस कार्य का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम में जिला कलैक्टर हरफूल

- ऐतिहासिक दरवाजों के संरक्षण कार्य का शुभारंभ आज होगा**
- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से स्वीकृति मिली**

सिंह यादव सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे। यह कार्य लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बूंदी में पर्यटन और विकास को गति देने के विजन को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा।

इंटेक चैप्टर बूंदी के संयोजक राजकुमार दाधीच ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा अध्यक्ष के विशेष प्रयासों से ही भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से इस कार्य को स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि इन ऐतिहासिक दरवाजों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण से न केवल शहर की



बूंदी शहर के ऐतिहासिक दरवाजों के संरक्षण व सौंदर्यीकरण का कार्य होगा।

सुंदरता में चार चांद लगेंगे, बल्कि देशी-विदेशी पर्यटन को भी नए पंख मिलेंगे। शहर की ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने के इस कार्य में आमजन से भी सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की गई है। इंटेक के सह-संयोजक राजेंद्र कुमार भारद्वाज, सदस्य नंद

प्रकाश शर्मा नंजी, अशोक तलवास, जेपी त्रिपाठी, पंकज दादी, मनमोहन अलमेरा, पीयूष पाचक और अनुराग शर्मा आदि ने शहरवासियों से इस संरक्षण कार्य में बढ़-चढ़कर सहयोग करने का आह्वान किया है।

क्षेत्र में अपराध की जिम्मेदारी आईजी व एसपी की होगी- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने संगठित अपराध, सायबर क्राइम व नशा तस्करी का पूरा नेटवर्क ध्वस्त करने के निर्देश दिए

जयपुर, 13 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर राज्य में कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में कानून व्यवस्था की बैठक में हाल की अपराधिक घटनाओं पर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल अरैस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाही पर आमजन का विश्वास बहाल करना पुलिस की जिम्मेदारी है।

अब क्षेत्र में होने वाले अपराधों की जिम्मेदारी सीधे संबंधित आईजी और एसपी की होगी। उन्होंने गृह विभाग एवं पुलिस अधिकारियों को दो टूक कहा कि प्रदेश में अपराध किसी भी सूरत में



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की।

बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों को फटकार लगाते हुए कहा कि संगठित अपराध, साइबर क्राइम और नशा तस्करी के मामलों में सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, बल्कि इन अपराधों का पूरा नेटवर्क ध्वस्त होना चाहिए। गोरगुदा में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण के मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी को उनके निर्देश पर नोटिस भी जारी किया गया। उन्होंने अलवर, श्रीगंगानगर और भरतपुर में हाल में हुई आपराधिक घटनाओं को

लेकर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध हथियार संगठित अपराध की रीढ़ है और संगठित अपराध को रोकने के लिए इसे तोड़ना बहुत जरूरी है। जिन जिलों में आम्स एन्ट के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, वहां अवैध हथियारों की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई कर आमजन का

विश्वास बहाल करना पुलिस की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध जघन्य अपराधों को अत्यंत गंभीर बताते हुए ऐसे मामलों में त्वरित, कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित, मुख्यमंत्री कार्यालय, गृह विभाग एवं पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, रैंज महानिरीक्षक एवं समस्त जिलों के पुलिस अधीक्षक वी.सी. के जरिए बैठक से जुड़े।

सोशल मीडिया ने नितिन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अनिवार्य बनाने की नीति के दौरान “सियान एग्री” की आय में तेज उछाल आया और उसके शेयरों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई। विपक्षी दलों और विश्लेषकों का कहना है कि यह हितों के टकराव का संभावित मामला हो सकता है। उनका सवाल है कि इस नीति को इतनी तेजी से लागू करने के पीछे जनहित है या निजी लाभ। गडकरी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके परिवार का चीनी और एथेनॉल से जुड़ा कारोबार पहले से चल रहा है और उन्हें इससे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं हो रहा है।

गडकरी एथेनॉल को देशहित के लिए बहुत जरूरी मानते हैं। उनका तर्क है कि एथेनॉल के उपयोग से तेल का आयात कम होता है, प्रदूषण घटता है,

गन्ने और अनाज की मांग बढ़ने से किसानों को फायदा होता है और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है। ब्राजील, अमेरिका और थाईलैंड जैसे देशों के सफल कार्यक्रमों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ई-20 तकनीकी रूप से सही साबित हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि इंजनों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने के दावे “पूरी तरह गलत हैं” और ऐसी आलोचनाओं के पीछे “पेट्रोलियम लॉबी” या उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे राजनीतिक विरोधियों का हाथ है, जो उनकी छवि खराब करना चाहते हैं।

गडकरी ने मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रहे दावों की भी गलत जानकारी और एक सोची-समझी मुहिम बताया है, जिसका उद्देश्य इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल को कमजोर

करना है। उन्होंने ऐसे संगठनों पर मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी भी दी है। यह पूरा मामला एक बड़े सवाल को सामने लाता है कि किसानों के हित और तेल आयात में कमी लाने, और दूसरी तरफ बुनियादी ढांचे की तैयारी, ग्राहकों की लागत और शासन की छवि के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। जहां एथेनॉल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, वहीं गडकरी परिवार के कारोबारी लाभ में पारदर्शिता को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। जब तक उपभोक्ताओं की शिकायतें जारी हैं और एथेनॉल उत्पादन में पानी की बढ़ती खपत को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, तब तक सरकार को स्वतंत्र और कड़ी जांच के साथ स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी, ताकि जनता का भरोसा बना रहे।

‘न्यायधीशों ने अपना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के बाद से हुई कई बैठकों के बाद जे डी ए ने स्वतः ही यह फैसला लिया कि वह तीन अनाधिकृत कॉलोनिजों का नियमितीकरण करेगी और इस संदर्भ में एन ओ सी भी जारी करेगी। जबकि अदालत के समक्ष कई सुनवाईयों में यह तथ्य भी सामने आये थे कि अतिक्रमण के कारण जयपुर मेट्रो के टोंक रोड पर बन रहे स्टेशनों के लिए रास्ता अवरुद्ध हो जायेगा।

अदालत ने तत्कालीन जेडीए कमिश्नर, शिखर अग्रवाल को अपने आदेश में नामजद करते हुए कहा कि उन्हें पता था कि उक्त सड़क के रास्ते में जेडीए की भूमि पर ही अतिक्रमण है परन्तु अतिक्रमणकारियों और गैर कानूनी निर्माणकर्ताओं को मदद करने के लिए जेडीए ने सड़क का अलाइनमेंट बदला है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में जेडीए द्वारा 2018 के जोनल प्लान को ही बदलने का फैसला किया गया और अदालत को भी जेडीए के वकीलों द्वारा सूचित किया गया। इस मामले की सुनवाई के दौरान जनहित याचिका दायरकर्ता अजय मार्ग निर्माण संघर्ष समिति की ओर से कहा गया कि संशोधित प्लान के अंदर सीधी सड़क के बदले एक 90 डिग्री का एक कोण बनाया गया है जिससे ट्रैफिक व्यवस्था में अड़चनें आएंगी और यह बदलाव केवल प्रभावशाली अतिक्रमणकारियों को सुरक्षा देने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन को अदालत को पारित नहीं होने देना चाहिए परन्तु वास्तविक जमीनी स्थिति को देखते हुए जेडीए कमिश्नर द्वारा 14 अगस्त 2025 को अदालत के समक्ष कहा गया कि वह संशोधित नक्शे को गजट नोटिफिकेशन के मार्फत जारी करना चाहती है। अदालत ने इस पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित हो, तब सड़क का अलाइनमेंट नहीं बदला जा सकता और किसी भी फेरबदल करने से पहले अदालत की अनुमति लेना आवश्यक है जो इस मामले में नहीं किया गया। कार्यकारी मुख्य न्यायधीश एस.पी. शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित ने अपने 13 अक्टूबर 2025 को दिए गए फैसले में कहा कि वर्ष



सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हत्तीघाटी रोड को जोड़ने वाली सॉ फीट रोड का मूल प्लान और नया प्लान।

2025 में ही हाउसिंग बोर्ड और जेडीए को आदेश दिए गए थे कि वह अतिक्रमणकारियों को हटाए परन्तु उनके रखैया से लगता है कि उनकी मंशा ही नहीं थी कि कभी ऐसा हो। इसके साथ ही अदालत ने जेडीए और हाउसिंग बोर्ड की रिएअलाइनमेंट करने की सुनवाई को सिर्रे से नकार दिया। और जेडीए को कहा कि वह सड़क निर्माण का कार्य मूल मास्टर प्लान के मुताबिक करे। इस आदेश के बावजूद इस पेचीदगियों से भरे मामले में सबसे रोचक मोड़ आना अभी बाकी था। दरअसल इस मामले के फैसले के बाद नाथू सिंह नामक एक व्यक्ति, जो मामले में 105 परिवारियों में से एक थे। ने अदालत के समक्ष अप्रैल 2026 में आवेदन पेश किया। इस आवेदन के अनुसार नाथू सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस पी शर्मा पेश हुए थे वर्ष 2013 में । अब जैसा कि विदित है कि कार्यकारी मुख्य न्यायधीश एस पी शर्मा की खंडपीठ ने ही 2025

में फैसला दिया था जो कि कानूनी प्रावधानों के विरुद्ध है। एक वकील जो एक मामले में पैरवी कर चुका हो वह उसी मामले में जज बनने के बाद फैसला नहीं दे सकता। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए कार्यकारी मुख्य न्यायधीश एस पी शर्मा और संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने अपने 2025 में दिए गए फैसले को “रि कॉल” किया और कहा कि यह मामला ऐसी खंडपीठ के समक्ष लग जाए, जिसका भाग कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस पी शर्मा न हो। उल्लेखनीय है कि इस आदेश के बाद यह मामला पुनः सुनवाई के लिए न्यायधीश इन्द्रजीत सिंह और न्यायधीश ध्रुवन गोयल के समक्ष सुनवाई बढ़ किया गया और इस अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 8 जुलाई को आदेश दिए कि जेडीए सड़क की रिएअलाइनमेंट के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर सकता है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष) में लाने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका ने ईरान के भीतर स्थित सैन्य प्रतिष्ठानों पर गहरे हमले करते हुए मिसाइल और ड्रोन सुविधाओं को निशाना बनाया है। यह ईरानी ठिकानों पर अमेरिका के नए सैन्य अभियान का दूसरा चरण माना जा रहा है। इससे पहले, पिछले सप्ताह अमेरिका ने लगभग 140 सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इनमें से अधिकांश ईरान के तटीय क्षेत्र में स्थित थे, जहां से होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर हमले किए जा रहे थे। ओमान के तट के पास से गुजरने वाले जहाज भी ईरानी हमलों से नहीं बच सके। ईरान ने सबसे पहले अमेरिका द्वारा स्वीकृत समुद्री मार्ग से गुजर रहे दो जहाजों पर हमला किया था। इनमें दो अत्याधुनिक और अत्यंत महंगे विशाल तेल टैंकर भी शामिल थे। इस घटना के बाद राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान की कड़ी आलोचना की और उन तटीय सैन्य परिसंपत्तियों को निष्क्रिय करने का आदेश दिया, जहां से ये हमले किए गए थे। अनेक देशों ने इन हमलों की निंदा की और दोनों देशों के बीच बढ़ते अविश्वास के कारण वार्ता का माहौल भी बिगड़ गया। बाद में ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि ईरान अपने वादों से पीछे हट रहा है और उसने अंतरिम

सरकार ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) उचित आरक्षण सुनिश्चित करना जरूरी है। ओबीसी आयोग ने 14 अगस्त, 2026 तक राजनीतिक आरक्षण रिपोर्ट पेश करने की सूचना दी है। ऐसे में सरकार विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण का विवरण 31 अगस्त तक उपलब्ध करा सकेगी। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने गत 6 जुलाई को पत्र के जरिए सूचित किया है कि यदि आरक्षण का विवरण 31 अगस्त तक उपलब्ध करा दिया जाएगा तो विभिन्न वैधानिक प्रावधानों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चार चरण में और निकाय चुनाव दो चरण में कराने होंगे और इसमें कुल 90 दिन का समय लगेगा। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि प्रदेश में करीब 14 हजार ग्राम पंचायतों और तीन सौ से अधिक नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। ऐसे में संसाधनों को देखते हुए चरणबद्ध चुनाव करना सही रहेगा। ग्राम पंचायत के चुनाव में 50 दिन और शहरी निकायों के लिए 40 दिन लगेगे।

सीमा के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जमीनी हकीकत, सुरक्षा सूचनाओं और तथ्यों का आंकलन कर हर मामले पर कार्यवाही करने के लिये उपयुक्त है। इस जानकारी के साथ यह कमेटी किसी भी ईमारत को तोड़ने या किसी भी व्यक्ति को ईमारत खाली करने तथा किसी भी अन्य तरह की कार्यवाही करने के लिये उपयुक्त है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में 22 याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की थी। और जिन्होंने बिना उपयुक्त इजाजत के भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास दरगाह, मस्जिद, मदरसे आदि का निर्माण किया था, जिसके लिए इन्हें नोटिफ दिए गए थे। इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से महाविधक्ता और केन्द्र सरकार की तरफ से एडिशनल सोलोसीजर जनरल पैरवी के लिये पेश हुये थे।

राजस्थान भर के ट्रांसपोर्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

प्रदेश के दस हजार ट्रकों के पहिए थमे, राज्य की सीमाओं पर 30-35 हजार ट्रक अटके

जयपुर, 13 जुलाई। वीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी),परमिट और ई-डिटेक्शन चालान से जुड़ी समस्याओं को लेकर राजस्थान के ट्रांसपोर्टर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदेशभर में करीब दस हजार ट्रकों ने चक्का जाम कर दिया है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि सरकार ने नियम तो लागू कर दिए, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं कीं, जिसका खामियाजा वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टरों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन को लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन, जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन, विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जयपुर परचून ट्रांसपोर्ट यूनियन और ऑल राजस्थान कॉन्ट्रेट कैरिज बस ऑपरेटर एसोसिएशन सहित, प्रदेश के कई प्रमुख ट्रांसपोर्ट संगठनों का समर्थन मिला है। अलवर में ट्रांसपोर्टरों ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बाजार की कुछ दुकानें भी बंद कराईं।

विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश चौधरी ने बताया कि प्रदेश में अधिकृत कंपनियों के पास पर्याप्त संख्या में वीएलटीडी डिवाइस उपलब्ध नहीं है। इसके कारण करीब 30

- ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि सरकार ने नियम तो लागू कर दिए, पर आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं कीं।
 - ट्रांसपोर्ट संगठनों का आरोप है कि राजस्थान में वीएलटीडी लगाने के लिए अधिकृत कंपनियां एक डिवाइस के 25-30 हजार वसूल रही हैं, जबकि अन्य राज्यों में यह डिवाइस 3 से 6 हजार रूपए में उपलब्ध है।
- से 3.5 हजार ट्रक राजस्थान की सीमाओं के बाहर खड़े हैं। यदि ये वाहन आवश्यक प्रक्रिया पूरी किए बिना राज्य में प्रवेश करते हैं तो ई-डिटेक्शन कैमरों के जरिए भारी-भरकम ऑनलाइन चालान होने का खतरा है। वहीं डिवाइस नहीं लगने से नेशनल परमिट और फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण भी अटका हुआ है। जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव गुलशन नागपाल ने कहा कि ट्रांसपोर्टर वीएलटीडी लगाने का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि इसे लागू करने के लिए पर्याप्त समय और व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रैकिंग डिवाइस लगने तक अस्थायी परमिट व्यवस्था जारी रखी जाए, ताकि मालवाहक वाहनों का संचालन बाधित न हो। ट्रांसपोर्ट संगठनों का आरोप है कि राजस्थान में केवल सीमित कंपनियों को वीएलटीडी लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। इन कंपनियों द्वारा एक डिवाइस के लिए 25 से 30 हजार रूपए तक वसूले जा रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों में यही डिवाइस करीब 3 से 6 हजार रूपए में उपलब्ध है। एसोसिएशन के प्रवक्ता राजीव त्रेहन ने कहा कि ई-डिटेक्शन प्रणाली के कारण बड़ी संख्या में लाखों रूपए के ऑनलाइन चालान हो रहे हैं। कई बार वाहन मालिकों को इसकी जानकारी तक नहीं होती और बाद में चालानों की लंबी सूची सामने आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरटीओ और पुलिस की कार्रवाई से ट्रांसपोर्टर लगातार परेशान हैं। केन्द्र सरकार ने एआईएस-140 सुरक्षा मानकों के तहत व्यावसायिक वाहनों में वीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य किया था। इसके बाद राजस्थान परिवहन विभाग ने वर्ष 2022 से इस व्यवस्था को लागू करना शुरू किया। ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति का कहना है कि यदि सरकार और ट्रांसपोर्ट संगठनों के बीच जल्द सहमति नहीं बनी तो प्रदेश में सीमेंट, स्टील, किराना, कृषि उपज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

.....जब शराब के ठेकेदारों का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) हस्तक्षेप नहीं है। फैसला कंप्यूटर करता है।” 2018 में योगी आदित्यनाथ द्वारा नई आबकारी नीति लागू किए जाने के बाद से शराब का लाइसेंस देने की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी हो गई। इससे रक्षपाल जैसे लोगों का काम आसान हुआ और राज्य के आबकारी राजस्व में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई। नई नीति लागू होने के पहले 10 महीनों में आबकारी राजस्व में 47.84 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2017-18 और 2018-19 के बीच साल-दर-साल 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तब से राज्य का आबकारी राजस्व लगातार बढ़ता रहा है। 2017-18 में 17,320 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में यह 57,722 करोड़ रुपये होगा। दस वर्षों में यह तीन गुना से भी अधिक हो गया और उत्तर प्रदेश आबकारी से सबसे अधिक राजस्व कमाने वाला राज्य बन गया। ऐसा नहीं था कि पहले कमाई की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश अपनी पूरी राजस्व क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा सरकारी खजाने तक पहुंचने से पहले शराब कार्टल के पास चला जाता था। राज्य को कम राजस्व मिलता था, जबकि ग्राहक ज्यादा कीमत चुकाता था। उत्तर प्रदेश में शराब की कीमतें उसके पड़ोसी राज्यों से ज्यादा

थीं, क्योंकि डिस्टिलरी और ब्रुअरी कई वर्षों तक लगभग बिना किसी रोक-टोक के अपनी “एक्स-डिस्टिलरी” कीमतों खुद तय करती थी। सीएजी की एक रिपोर्ट के अनुसार, पहले 750 मिलीलीटर की एक सामान्य रम की बोतल उत्तर प्रदेश में राजस्थान की तुलना में 102.28 रुपये महंगी थी। लेखा परीक्षक ने 2008 से 2018 के बीच डिस्टिलरी मालिकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को 7,168 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ मिलने की बात कही थी। अब तस्वीर बदल चुकी है। अब उत्तर प्रदेश अपने सभी पड़ोसी राज्यों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करता है और कई जॉड उनसे भी कम कीमत पर उपलब्ध कराता है। कीमतों में बदलाव का असर रक्षपाल की दुकान पर भी दिखाई देता है। उनकी दुकान रामपुर के बाहरी इलाके में नैनीताल जाने वाली सड़क पर है। वे बताते हैं कि पहाड़ों की ओर जाने वाले पर्यटक रास्ते में उनकी दुकान से शराब खरीदते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में प्रवेश करने के बाद शराब महंगी हो जाती है। शराब कार्टल के कमाने देने के बजाय, उत्तर प्रदेश सरकार ने वह हिस्सा अपने पास रखा। साथ ही अवैध शराब भी बिक्री पर नियंत्रण करके राजस्व बढ़ाने का दूसरा रास्ता भी अपनाया। राज्य ने पूरी आपूर्ति श्रृंखला में “ट्रैक एंड ट्रेस” प्रणाली लागू की। हर बोतल पर

एक कोड लगाया गया, ताकि डिस्टिलरी से बिक्री केन्द्र तक कहीं भी गड़बड़ी न हो। इससे आबकारी अधिकारियों को तस्करी की शराब और वैध शराब में अंतर पहचानने में भी मदद मिली। पेशे से मधुमक्खी पालक मुकेश पाठक, जिन्होंने रक्षपाल को शराब का लाइसेंस लेने की सभी औपचारिकताएं पूरी करने में मदद की, बताते हैं, “हर बोतल के लेबल पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन किए बिना एक भी बोतल नहीं बेची जा सकती। इसमें देशी शराब भी शामिल है।” वे आगे कहते हैं, “इससे कम से कम दुकानों पर अवैध शराब की बिक्री खत्म हो गई है। पहले बिक्री का एक तथ्य कोटा होता था। जिनकी बिक्री कम होती थी, उन्हें अपना कोटा पूरा करने की चिंता रहती थी, जबकि जिनकी बिक्री अच्छी होती थी, वे अपने कोटे से अधिक अवैध शराब भी बेचते थे।” वे आगे बताते हैं कि अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के अलावा यह व्यवस्था यह भी सुनिश्चित करती है कि रात 9 या 10 बजे के बाद या ड्राइव डे के दिन कोई बिक्री न हो। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई ने क्यूआर कोड व्यवस्था को और मजबूत किया है। केवल महं महीने में ही अवैध शराब से जुड़े लगभग 9,900 मामले दर्ज किए गए और 2.29 लाख लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त की गई।

प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर बैकफुट पर है- सचिन पायलट

पायलट ने बाँसवाड़ा में दावा किया कि बड़ी संख्या में प्रधान, सरपंच व जिला प्रमुख कांग्रेस के बनेंगे

बाँसवाड़ा, 13 जुलाई। एआईसीसी महासचिव व प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर बैकफुट पर है। पंचायती राज और निकाय चुनाव नहीं कराना उसके डरे होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। पायलट ने यह बात बाँसवाड़ा दौरे के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कही। पायलट ने कहा कि प्रदेश में वैचारिका एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बिगड़ी हालात में है और प्रदेश की जनता ने सरकार रवानगी तय कर दी है। एक सवाल के जवाब में पायलट ने केन्द्र और राज्य सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया तथा कहा कि ईडी और चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं भी वैमनस्य की भावना से कार्यवाही कर रही हैं।

पायलट ने अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी प्रकरण पर भी सवाल उठाये और कहा कि यही लोग कहते थे कि न खाऊंगा, न खाने दूंगा, लेकिन राम मंदिर में आये चंदे पर भी माल चंपत करके चंपत हो गये। पायलट ने कहा प्रदेश में कांग्रेस एकजुट है और पार्टी का एके-एक कार्यकर्ता मजबूती से आगामी दिनों में होने वाले पंचायती



कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का कुशलगढ़ में कार्यकर्ताओं ने हल भेंट कर भव्य स्वागत किया।

राज व नगर निकाय चुनावों में शानदार जीत के लिये जुटा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बड़ी मात्रा में प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख कांग्रेस के बनेंगे वाले हैं। बागडू में बाप पार्टी पर अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि हर एक

राजनैतिक दल का अपना एक नजरिया होता है और राजनैतिक पार्टियां अपने तौर तरीकों व विचारधारा से बनती, आगे बढ़ती और बिगड़ती रही हैं। इस दौरान बाँसवाड़ा विधायक व पाटी जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया,

विधायक नानालाल निनामा, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, पूर्व उप जिला प्रमुख डॉ. विकास बामनिया, संगठन महासचिव मनीष पुन त्रिवेदी, अब्दुल गफ्फार, पूर्व संपादित राजेश टेनर, नवाब खां फौजदार, नगर कांग्रेस

- पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कुशलगढ़ में पूर्व प्रधान हर्दयस खडिया के श्रद्धांजलि समारोह में भी भाग लिया।

अध्यक्ष धर्मेन्द्र तेली, अतीत गरासिया, पूर्व प्रधान सुनिता माल सहित अनेक नेता मौजूद रहे। इससे पूर्व सर्किट हाउस पहुंचने पर सैकड़ों की संख्या में उमड़े युवा कार्यकर्ताओं ने जोशीले नारे लगाते हुए सचिन पायलट का स्वागत किया। पायलट ने भी सभी कार्यकर्ताओं के सम्मान को स्वीकारा। देर रात तक सर्किट हाउस में मेला लगा रहा। इससे पूर्व, उन्होंने कुशलगढ़ में पूर्व प्रधान हरुतिंग खडिया के श्रद्धांजलि समारोह में भाग लिया। कुशलगढ़ में भी पायलट की एक झलक पाने के लिये कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह नजर आया। कार्यक्रम में पूर्व केबिनेट मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, स्थानीय नेता हंसमुख सेठ आदि मौजूद थे।